द शूटर

सूरजपुर जिले से प्रकाशित
प्रथम हिन्दी दैनिक

प्रधान संपादक- रुपेश दुबे: 9826169678
संपादक- प्रवीण दुबे: 9165083700

वर्ष-14 अंक-170 | प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर छ.ग. से प्रकाशित | शुक्रवार 07 अगस्त 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य- 2 रूपये

रिहाई के बाद फिर सलाखों के पीछे पहुंचे 10 आरोपी, अपहरण और हत्या के बहुचर्चित मामले में पुलिस की कानूनी लड़ाई रंग लाई

सूरजपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर।

प्रतापपुर थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवक की बेरहमी से पिटाई और हत्या के बहुचर्चित मामले में न्यायिक प्रक्रिया ने नया मोड़ ले लिया। पहले निजी मुचलके पर रिहा किए गए 10 आरोपियों को अब दोबारा गिरफ्तार कर 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रतापपुर पुलिस द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका स्वीकार होने के बाद न्यायालय ने पूर्व आदेश निरस्त कर दिया, जिससे इस गंभीर प्रकरण में पुलिस की कानूनी पहल को बड़ी सफलता मिली है।मामले की शुरूआत 24 जुलाई 2026 को हुई, जब ग्राम गोंदा निवासी सम्पतिया सूर्यवंशी ने थाना प्रतापपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले रात करीब साढ़े आठ बजे हरिनन्दन राजवाड़े अपने दो साथियों के साथ उनके घर आया था। बातचीत के दौरान अचानक ग्राम केंवरा के ललित राजवाड़े सहित कई लोग सात मोटरसाइकिलों पर सवार होकर पहुंचे और घर में घुस गए। आरोप है कि सभी ने मिलकर हरिनन्दन के साथ गाली-गलौज की, उसे डंडों और हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए जबरन घर से बाहर खींच ले गए।

शिकायतकर्ता के अनुसार उन्होंने और उनके पति ने बीच-बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद हरिनन्दन को मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले जाया गया। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 को दी गई और पीड़ित परिवार ने आरोपियों का पीछा किया। भैंसामुड़ा के केंवरा चौक के पास हरिनन्दन गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा मिला, जहां से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में इस मामले में हत्या सहित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक आईपीएस योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर प्रतापपुर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से विवेचना की। घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान, मर्ग दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाने के बाद 27 जुलाई को 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यपालिक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पीड़ित पक्ष से आरोपियों की शिनाख्त कराई गई। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तीन डंडे और चार मोटरसाइकिल जब्त की गईं।हालांकि प्रारंभिक सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस के रिमांड आवेदन को अस्वीकार करते हुए सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए प्रतापपुर पुलिस ने जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रतापपुर ने पुलिस की दलीलों पर सहमति जताते हुए पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया।गुरुवार को पुलिस ने सभी आरोपियों को दोबारा न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उन्हें 20 अगस्त 2026 तक 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।

गंभीर अपराधों में प्रभावी विवेचना, मजबूत साक्ष्य और सतत कानूनी प्रयास किस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा दे सकते हैं, प्रतापपुर का यह मामला उसकी एक महत्वपूर्ण मिसाल बनकर सामने आया है।

सेवानिवृत्त 12 शिक्षकों को सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति आदेश जारी

अम्बिकापुर 06 अगस्त 2026/ छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, रायपुर से प्राप्त निदेर्शों के अनुपालन में विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवानिवृत्ति उपरांत सत्रांत तक पुनर्नियुक्ति प्रदान की जानी है। इसी क्रम में सरगुजा जिले में माह जून एवं जुलाई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों से पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र एवं आवश्यक अभिलेख प्राप्त किए गए थे।

प्राप्त आवेदनों एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत पात्र 12 शिक्षकों को जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा, अंबिकापुर द्वारा पुनर्नियुक्ति आदेश प्रदान किया गया।

पुनर्नियुक्ति आदेश प्राप्त करने वाले शिक्षकों में श्रीमती निर्मला कश्यप, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. असोलाय ओम प्रकाश गुप्ता, व्याख्याता, सेजेस उदयपुरय श्रीमती नीता सिंह, व्याख्याता, शा.उ.मा.वि. करजीय योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता, प्रधान पाठक, शा.प्राथ.शाला बकमेर अम्बिका प्रसाद सोनी, प्रधान पाठक, शा.माध्य.शाला रघुनाथपुर उदय शंकर श्रीवास्तव, प्रधान पाठक, शा.प्राथ.शाला चठिरमा जमील अहमद फिरदौसी, प्राचार्य, शा. हाईस्कूल डड़गांवय जगदीश सिंह, प्रधान पाठक, शा.माध्य.शाला कन्या खम्हरिया अनिल राम प्रजापति, प्रधान पाठक, शा.प्राथ.शाला केनाडांड श्रीमती श्याम प्यारी बुनकर, प्राचार्य, शा. हाईस्कूल महेशपुर श्रीमती संजुला श्रीवास्तव, शिक्षक, शा.माध्य.शाला अजिरमा तथा श्री कृष्ण कुमार अचगले, प्रधान पाठक, शा.प्राथ.शाला सुमेरपुर शामिल हैं।

इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने पुनर्नियुक्ति प्राप्त शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं तथा विद्यालयों में विद्यार्थियों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और अधिक ऊर्जा एवं उत्साह के साथ अध्यापन कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षकों से अपने अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं सीखने के स्तर को बेहतर बनाने कहा।

10 दिन तक पुलिस को छकाता रहा आरोपी, आखिर पटना से गिरफ्त में आया नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपित

अम्बिकापुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर।

नाबालिग से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार सरगुजा पुलिस ने करीब 10 दिनों की लगातार तलाश और तकनीकी निगरानी के बाद बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार शहर और राज्य बदलता रहा, मोबाइल बंद रखता था और राहगीरों के मोबाइल से संपर्क कर अपनी लोकेशन छिपाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः पुलिस की रणनीति के आगे उसकी हर चाल नाकाम हो गई।थाना कोतवाली अम्बिकापुर में दर्ज अपराध क्रमांक 504/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के मामले में आरोपी तरुण कुमार जायसवाल (51 वर्ष) निवासी भफौली, अंबिकापुर घटना के बाद से फरार था। मामले की गंभीरता को देखते हुए

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा आईपीएस राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देशन में दो विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी में सहयोग करने वाले के लिए 5 हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के संभावित सभी ठिकानों पर दबिश दी। उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, बैंक खाते फ्रीज कराए गए, वाहन की ट्रैवल हिस्ट्री और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की तकनीकी जानकारी जुटाई गई। जांच में पता चला कि आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदलते हुए देवघर, वासुकीनाथ, पुरी और रांची पहुंचा, लेकिन पुलिस टीम भी उसके पीछे लगातार लगी रही।

आखिरकार पटना में आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि होने पर सरगुजा पुलिस ने बिहार पुलिस के सहयोग से उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड के लिए पटना की अदालत में पेश किया गया, जहां से अनुमति मिलने के बाद उसे अंबिकापुर लाया जा रहा है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

पुलिस ने आरोपी के नाम से जारी 12 बोर डीबीबीएल लाइसेंसी बंदूक और उसका लाइसेंस भी पहले ही जब्त कर लिया था। बताया गया कि उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर के नेतृत्व में गठित विशेष टीम की सतत निगरानी, तकनीकी विश्लेषण और विभिन्न राज्यों की पुलिस के समन्वय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने और ऐसे गंभीर अपराधों में आरोपियों को कानून के शिकंजे तक पहुंचाने के लिए अभियान आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगा।

स्मार्ट मीटर से लेकर महंगाई तक के मुद्दों पर कांग्रेस का मंथन, कार्यकताओं से जनसंवाद बढ़ाने का आह्वान

अम्बिकापुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर।

आने वाले राजनीतिक संघर्ष की तैयारी और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा ने एक वृहद संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया। करीब पांच घंटे तक चली इस कार्यशाला में केवल भाषण नहीं हुए, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष, मोर्चा-संगठनों के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि यदि कांग्रेस को फिर से सरकार बनानी है तो संगठन को प्रत्येक बूथ तक मजबूत करना होगा और अपने पक्ष में कम से कम 40 प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में जिन समस्याओं से आम नागरिक परेशान हैं, उनकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों पर है। उन्होंने नोटबंदी, परीक्षा पत्र लीक, बेरोजगारी, महंगाई, इथेनॉल नीति, स्मार्ट मीटर और भगवान श्रीराम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े विवाद जैसे मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन विषयों पर जनता के बीच तथ्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाना चाहिए।पूर्व निगम सभापति अजय अग्रवाल ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का संकल्प है। उन्होंने कार्यकताओं से घर-घर जाकर मतदाताओं से संवाद बढ़ाने और कांग्रेस सरकार के समय संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। उनका कहना था कि जनता में मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष दिखाई दे रहा है और इस भावना को सकारात्मक संवाद के माध्यम से संगठन की ताकत में बदला जा सकता है।प्रदेश महामंत्री द्वितेंद्र मिश्रा ने संगठन की कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रशिक्षण देते हुए कहा कि बूथ, पंचायत, वार्ड और मंडल स्तर की प्रत्येक इकाई में जिम्मेदारियां स्पष्ट हों और कार्यकताओं का नियमित मार्गदर्शन किया जाए, तभी संगठन प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने प्रदेश में चल रहे स्मार्ट मीटर विरोधी अभियान के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पिछले तीन दिनों के जनसंपर्क अभियान में उपभोक्ताओं ने कांग्रेस के हस्ताक्षर अभियान और विरोध फॉर्म को लेकर उत्साह दिखाया है। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं स्वयं आगे बढ़कर स्मार्ट मीटर पर विरोध संबंधी स्टिकर लगा रही हैं। उन्होंने सरगुजा जिले में बढ़ती बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत कई विद्युत उपकेंद्रों की योजनाएं आगे नहीं बढ़ सकीं, जिसके कारण आज उपभोक्ताओं को बिजली की अव्यवस्था और बढ़े हुए बिजली बिल, दोनों का सामना करना पड़ रहा है।पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने एग्री स्टेट पंजीयन, राशन वितरण व्यवस्था और विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अरविंद सिंह एवं महामंत्री हेमंत तिवारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में दीवानी, फौजदारी और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में लोगों की सहायता करने तथा जटिल मामलों को जिला नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रक्रिया समझाई।जिला कांग्रेस महामंत्री जमील खान ने मतदाता सूची के नियमित परीक्षण, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम विलोपित कराने और स्थानांतरण की प्रक्रिया की जानकारी दी। वहीं महामंत्री अनूप मेहता ने सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, मीडिया से संवाद और कनेक्ट कांग्रेस अभियान के माध्यम से संगठन की गतिविधियों को अधिक व्यापक बनाने पर प्रशिक्षण दिया।पूरी कार्यशाला व्याख्यान और सवाल-जवाब की शैली में आयोजित की गई, जिसमें कार्यकताओं ने विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में संगठन गांव-गांव और बूथ-बूथ तक पहुंचकर जनसंपर्क अभियान को और तेज करेगा तथा स्मार्ट मीटर, महंगाई, बेरोजगारी और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी।

500 करोड़ के एआई मिशन से बदलेगी छत्तीसगढ़ की डिजिटल तस्वीर : भाजपा

*** भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हार्दिक आभार माना**

अम्बिकापुर। द शूटर।

भाजपा सरगुजा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मिशन को दी गई ऐतिहासिक मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देने वाला एक दूरदर्शी निर्णय बताया है। श्री सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश के डिजिटल रोडमैप को धरातल पर उतारने के नाम पर केवल जुबानी जमाखर्च किया जबकि भाजपा की साय सरकार का वास्तविक धरातल पर काम नजर आ रहा है।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्री सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार का यह मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। यह मिशन न केवल बड़े शहरों तक सीमित रहेगा, बल्कि इसका मुख्य फोकस राज्य के दूर-दराज के जिलों, छोटे शहरों और कस्बों तक एआई की पहुँच सुनिश्चित करना है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। इस योजना के मुख्य बिन्दुओं की चर्चा करते हुए भारत सिंह सिसोदिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन के तहत राज्यभर में अत्याधुनिक 100 एआई डेटा लैब का निर्माण किया जाएगा। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। युवाओं के नवाचार को बल देने के लिए 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य के 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासकीय कामकाज को सुगम, पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए 50 से अधिक एआई-आधारित सेवाओं का विकास होगा।

उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग हमेशा यह राग अलापते रहते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पूरे देश को कम्प्यूटरीकृत करने का सपना देखा था। लेकिन सच्चाई यह है कि दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेसी सरकारों ने उनके सपनों को धरातल पर साकार करने की जरा भी पहल नहीं की। कांग्रेस ने तकनीक के नाम पर केवल बातें कीं, जबकि भाजपा की साय सरकार ने नीतियों को जमीन पर उतारकर यह साबित कर दिखाया है कि सुशासन और डिजिटल परिवर्तन कैसे लाया जाता है ! श्री सिसोदिया ने कहा कि यह मिशन भारत सरकार के इण्डिया एआई मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को एक उत्तरदायी, नवाचार-आधारित और भविष्य-उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

कमिश्नर के आदेश के बाद हरकत में आया प्रशासन, बैकुण्ठपुर उप पंजीयक कार्यालय को जारी हुआ नोटिस

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के बैकुण्ठपुर स्थित उप पंजीयक (रजिस्ट्रार) कार्यालय में कथित रूप से शासकीय एवं अन्य विवादित भूमि की रजिस्ट्री के मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। लंबे समय तक स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के बाद मामला सरगुजा संभाग आयुक्त (कमिश्नर) कार्यालय पहुंचा, जहां से 20 जुलाई 2026 को पत्र क्रमांक 4623 जारी कर संबंधित शिकायत पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय बैकुण्ठपुर द्वारा उप पंजीयक कार्यालय को नोटिस जारी कर निर्धारित समय सीमा में जानकारी एवं जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बैकुण्ठपुर उप पंजीयक कार्यालय में ऐसे कई भूमि खसरा नंबरों की रजिस्ट्री की गई है, जिन्हें राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि, जंगल मद अथवा पट्टेदार भूमि के रूप में दर्ज बताया गया है। शिकायत के आधार पर विभिन्न पटवारियों से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें कई मामलों में संबंधित भूमि की प्रकृति को शासकीय अथवा अन्य श्रेणी का बताया गया। इन तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया नियमों के उल्लंघन की आशंका व्यक्त की गई है, जिसके बाद विस्तृत जांच की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। सूत्रों के अनुसार, एसडीएम कार्यालय ने उप पंजीयक कार्यालय से संबंधित अभिलेख, रजिस्ट्री प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की

जानकारी मांगी है। निर्धारित समय के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच की जा सके।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि प्रारंभिक शिकायत पर ही कोरिया जिला स्तर पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई कर दी जाती, तो उन्हें कमिश्नर कार्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब होने के कारण उन्हें उच्च अधिकारियों के समक्ष गुहार लगानी पड़ती है।

शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि यह अकेला मामला नहीं है। उनके अनुसार, कोरिया जिले से संबंधित कई शिकायतों में स्थानीय स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण उन्हें सरगुजा संभाग आयुक्त कार्यालय, अंबिकापुर का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनका कहना है कि कई मामलों में कमिश्नर कार्यालय से निर्देश जारी होने के बाद ही संबंधित विभाग एवं जिला प्रशासन सक्रिय होकर कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि मामले की जांच नियमानुसार की जा रही है तथा अंतिम निष्कर्ष जांच पूर्ण होने के बाद ही सामने आएगा। यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन अथवा लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सामने आए इस प्रकरण में एसडीएम कार्यालय द्वारा उप पंजीयक को नोटिस जारी किए जाने के बाद यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में शिकायतों की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होने के साथ-साथ भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र में न्यायालय संचालन और भूमि अभिलेखों पर उठे सवाल, कलेक्टर से एफआईआर दर्ज कराने की मांग

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिले के अनुसूचित क्षेत्र में न्यायालय संचालन, राजस्व अभिलेखों के लेखन तथा भूमि क्रय-विक्रय की वैधता को लेकर एक विस्तृत शिकायत कलेक्टर को सौंपते हुए संबंधित अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मामलों में विधि के अधिकार क्षेत्र के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जिससे संविधान एवं कानून की भावना प्रभावित हो रही है। शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 467, 468 एवं 471 सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। आवेदन में अनुसूचित क्षेत्रों के ऐतिहासिक एवं संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोरिया जिला संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र है और यहां लागू होने वाले कानूनों एवं प्रशासनिक अधिकारों का पालन आवश्यक है। शिकायतकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के पुराने निर्णयों, अनुसूचित क्षेत्र संबंधी

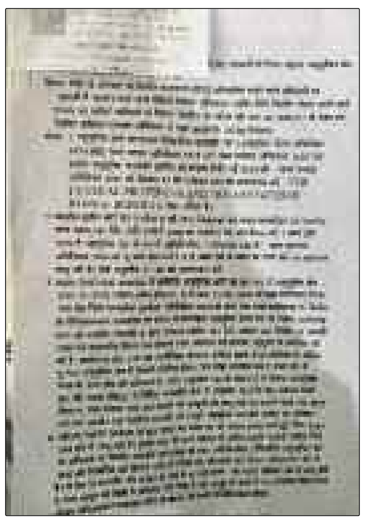

अधिसूचनाओं तथा राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि संबंधित क्षेत्र में कई प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही वैधानिक अधिकार क्षेत्र के अनुरूप नहीं की जा रही हैं। आवेदन में यह भी कहा गया है कि भूमि अभिलेखों में कथित रूप से नियमों के विपरीत प्रविष्टियां दर्ज की गई हैं और कुछ मामलों में शासकीय भूमि तथा निजी भूमि से जुड़े रिकॉर्ड में अनियमितताएं सामने आई हैं। शिकायत में एक राजस्व प्रकरण का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि के स्वामित्व, सीमांकन एवं नामांतरण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि संबंधित भूमि के क्रय-विक्रय एवं पंजीयन की वैधता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि कुछ अधिवक्ताओं द्वारा ऐसे मामलों में वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जबकि शिकायतकर्ता के अनुसार संबंधित क्षेत्र में इसकी वैधानिक स्थिति पर विवाद है। इस आधार पर अधिवक्ताओं तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ता के स्वयं के दावे हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि अथवा जांच रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। अब यह देखना होगा कि जिला प्रशासन शिकायत पर क्या निर्णय लेता है और मामले की जांच किस स्तर पर कराई जाती है।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने विद्यार्थियों में भरा आत्मविश्वास, कहा- बड़ा सपना देखें, मेहनत से उसे साकार करें

बैकुण्ठपुर। जिला कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने बुधवार को पोड़ी स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर विद्यार्थियों से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को संकोच छोड़कर खुलकर अपनी बात रखने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए ईमानदारी एवं निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। विद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने औपचारिक माहौल को सहज बनाते हुए कहा, आज मैं छात्रा बनती हूं और आप सब शिक्षक। इसके बाद उन्होंने विज्ञान एवं कला संकाय के विद्यार्थियों से विषय आधारित प्रश्न पूछे। विज्ञान के विद्यार्थियों से वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा की गई, वहीं कला संकाय के विद्यार्थियों से संविधान, मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्वों से जुड़े प्रश्न पूछकर उनकी समझ का आकलन किया। कलेक्टर ने विद्यार्थियों

से कहा कि गलत उत्तर देने के डर से कभी चुप न रहें। जो पढ़ा है, उसे आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करें। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को करियर के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने की सलाह देते हुए कहा कि करियर का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वकील, पुलिस अधिकारी या अन्य किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट भविष्य बनाया जा सकता है। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी प्राप्त करने की भी उन्होंने सलाह दी। कृषि क्षेत्र को भी उन्होंने युवाओं के लिए बेहतर संभावनाओं वाला क्षेत्र बताया। संवाद के दौरान कलेक्टर ने शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों को अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं और उनकी मजबूत शैक्षणिक नींव तैयार करें। केवल पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सामान्य ज्ञान, तार्किक सोच और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता विकसित करना भी आवश्यक है। विद्यालय निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर की समीक्षा की। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर उन्होंने प्राचार्य को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए आवश्यक सुधार करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने विद्यालय में प्रत्येक शनिवार सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित विशेष गतिविधियां और चर्चा आयोजित करने के निर्देश भी दिए, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य की प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए प्रारंभ से ही तैयार किया जा सके। कलेक्टर रोक्तिमा यादव के इस प्रेरणादायी संवाद से विद्यार्थियों में उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिला। उन्होंने अंत में विद्यार्थियों से कहा कि बड़ा सपना देखने में कभी संकोच न करें। लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए पूरी ईमानदारी, अनुशासन और निरंतर मेहनत के साथ आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी।

मेहनत, अनुशासन और खेल भावना आगे बढ़ने का सशक्त माध्यम - योगेश पटेल

*** इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज**

सूरजपुर/द शूटर।

साधु राम विद्या मंदिर सूरजपुर द्वारा आयोजित एमपावर इंटरस्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ गुरुवार को विद्यालय परिसर में भव्य उद्घाटन समारोह पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के गरिमामयी आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ खिलाड़ियों के परिचय के साथ, फ्लैग होस्टिंग, दीप प्रज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने खेल भावना, अनुशासन एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकल्प लिया।

उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के साथ विशिष्ट अतिथि में एमपावर के डायरेक्टर गोविंद मुदलियार, एमपावर की एचआर सुश्री निधि, साधु राम विद्या मंदिर के डायरेक्टर डॉ. राहुल अग्रवाल, एसएमसी अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, पूर्व पार्षद संजय डोसी, विद्यालय की प्राचार्या खुशबू सिंह तथा उप-प्राचार्य दीन दयाल तिवारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह का संचालन तुलेश्वर राजवाड़े, दीपक पटले व निदा फाजली रही। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री पटेल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास का माध्यम हैं, बल्कि अनुशासन,नेतृत्व व टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना भी विकसित करता हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं और कहा कि न तो हार से घबराना है।

न जीत पर इतराना है। बच्चो के साथ अपनी पढ़ाई का समय और यूपीएससी के अनुभवों को साझा किया व कहा कि स्कूली शिक्षा में नकारात्मकता को छोड़ कर सकारात्मक पर फोकस करें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में निरंतर आगे बढ़े। वही टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच कोलंबिया ग्लोबल स्कूल, रायपुर एवं रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल, गोंदिया के मध्य खेला गया। दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद विजेता का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल, गोंदिया ने 3-1 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में विजयी शुरूआत की। उद्घाटन समारोह में विद्यालय परिवार, प्रतिभागी विद्यालयों के शिक्षक, प्रशिक्षक, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में उत्साह, खेल भावना एवं अनुशासन के उत्कृष्ट वातावरण में तीन दिनों तक चलेगा। टूर्नामेंट का समापन व फाईनल मुकाबला 08 अगस्त को खेला जायेगा।

निजी भूमि के कथित अवैध नामांतरण व बिक्री का आरोप, किसान ने 90 पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ कलेक्टर से की शिकायत

सूरजपुर। भैयाथान के तत्कालीन तहसीलदार रहे संजय राठौर के खिलाफ निजी स्वामित्व की भूमि के कथित अवैध नामांतरण और बिक्री का गंभीर मामला सामने आया है। किसान दीपेश दुबे ने कलेक्टर जनदर्शन में लगभग 90 पृष्ठों के दस्तावेज प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनकी निजी भूमि का बिना सूचना, बिना सहमति और विधिक प्रक्रिया का पालन किए नामांतरण कर कुछ व्यक्तियों के पक्ष में दर्ज कर दिया गया तथा बाद में भूमि की बिक्री भी करा दी गई। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, भूमि की पुनर्बहाली तथा दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार वर्ष 1983 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, केवरा द्वारा आयोजित सार्वजनिक नीलामी में दीपेश दुबे को ग्राम कोयलारी की संबंधित भूमि का क्रेता घोषित किया गया था। वर्ष 1985 में सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा इसकी पुष्टि की गई और 1987 में राजस्व अभिलेखों में उनका नाम विधिवत दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके बाद से लगातार विभिन्न वर्षों के बी-1 अभिलेखों में उनका नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज रहा, यहां तक कि खसरा नंबरों के पुनर्नंबरिंग के बाद भी स्वामित्व यथावत बना रहा।

आरोप है कि वर्ष 2024-25 के दौरान भैयाथान में पदस्थ रहते हुए तत्कालीन तहसीलदार संजय राठौर ने कथित रूप से कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर उनकी निजी भूमि को संयुक्त खाते की भूमि मानते हुए बिना किसी वैधानिक सूचना या सुनवाई के नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिस आवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई, उसमें संबंधित खसरा नंबरों का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं था, फिर भी उनकी निजी भूमि को विवादित प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि नामांतरण के बाद भूमि के कुछ हिस्सों का पंजीकृत विक्रय भी करा दिया गया। साथ ही यह दावा किया गया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान कई राजस्व अभिलेखों में अनियमितताएं हुईं, कुछ दस्तावेजों में कथित रूप से फर्जी हस्ताक्षरों का उपयोग किया गया तथा जीवित और मृत खातेदारों के संबंध में भी रिकॉर्ड में गंभीर त्रुटियां की गईं। शिकायतकर्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि संजय राठौर के विरुद्ध पूर्व में भी अन्य भूमि संबंधी मामलों में कार्रवाई हो चुकी है तथा कुछ प्रकरणों की विभागीय जांच और न्यायालयीन कार्यवाही लंबित है। हालांकि इन मामलों में अंतिम निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार अथवा न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। दीपेश दुबे ने कलेक्टर सूरजपुर से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, कथित रूप से अवैध नामांतरण और विक्रय को निरस्त कर उनकी भूमि उन्हें वापस दिलाई जाए तथा यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय कानून के अनुसार आपराधिक एवं विभागीय कार्रवाई की जाए।k

संत रविदास की जन्मस्थली की पावन मिट्टी से युक्त कलश एवं रथ का सरगुजा में भव्य स्वागत

अम्बिकापुर। द शूटर।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर में आयोजित कलश वंदन एवं वितरण समारोह से प्राप्त संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पावन मिट्टी से युक्त कलश एवं रथ के सरगुजा आगमन पर भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं ने श्रद्धापूर्वक पूजन-अर्चन एवं स्वागत किया।

इसके उपरांत पवित्र कलश एवं रथ को नगर स्थित श्री हनुमान मंदिर में अस्थायी रूप से स्थापित किया गया। संत रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर यह पवित्र कलश जिले के विभिन्न मंडलों एवं ग्रामों में भ्रमण करेगा तथा उनके सामाजिक समरसता, समानता एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगा।

इस दौरान महापौर मंजूषा भगत, फुलेश्वरी सिंह, विनोद हर्ष, मधु चौदाहा, निश्चल प्रताप सिंह, शुभांगी बिहाडे, ममता कश्यप , शोभा शर्मा , बबलू गुप्ता, सावित्री जयसवाल, शकुंतला पांडे, नीलम राजवाड़े, बबली नेताम, रजनी बिंद, रश्मि जयसवाल, प्रियंका चौबे, नीलू गुप्ता,अर्चना सिंह, रेनू भारती, सरस्वती यादव, शालिनी सिंह, रीना राय, नलिनी पांडे, रूपा गुप्ता, पंकज गुप्ता, रवि विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

अग्रवाल महिला मंडल का सर्वसम्मति से गठन, ममता अग्रवाल बनीं अध्यक्ष

सूरजपुर/द शूटर।

अग्रवाल महिला मंडल की बैठक में नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से श्रीमती ममता अग्रवाल को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नई कार्यकारिणी में सीमा गर्ग को सचिव, रिंकी अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, सुमन गोयल एवं सोनू अग्रवाल को उपाध्यक्ष, सीमा गोयल को सह सचिव तथा काजल अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया।

संरक्षक मंडल में श्रीमती नयनकला गर्ग, कमलेश गोयल, लता गोयल, ललिता तायल, मीना गोयल, आशा अग्रवाल एवं विजया गर्ग को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मीरा अग्रवाल, मंजू गोयल, सपना अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, सोमिल अग्रवाल, गीता अग्रवाल, रेनी अग्रवाल, रेखा गोयल, उषा अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, नीता गोयल, कनक गोयल, पिंकी गोयल, कुसुम अग्रवाल, स्वाति गोयल, विधि अग्रवाल एवं पिंकी केजरीवाल को शामिल किया गया। इस अवसर पर सभी नव-निर्वाचित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं। बैठक में सभी ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को मिल-जुलकर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने नई कार्यकारिणी के प्रति पूर्ण सहयोग एवं विश्वास व्यक्त करते हुए अग्रवाल समाज की सेवा के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।

औचक निरीक्षण में दिखी पढ़ाई की गुणवत्ता, इको क्लब के हरियाले प्रयासों ने भी जीता सहायक संचालक का दिल

रामानुजनगर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। विद्यालय केवल भवन और कक्षाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि वहीं से अनुशासन, संस्कार और भविष्य की नींव तैयार होती है। इसी सोच को परखने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले के सहायक संचालक अजय सिंह ने विकासखंड रामानुजनगर अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला पटना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों और विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान सहायक संचालक विभिन्न कक्षाओं में पहुंचे और विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम से जुड़े प्रश्न पूछकर उनके अध्ययन स्तर का मूल्यांकन किया। बच्चों के उत्तरों और आत्मविश्वास से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया।शिक्षकों से चर्चा करते हुए अजय सिंह ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, सतत मूल्यांकन और नवाचारी शिक्षण पद्धतियों को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को रचनात्मक प्रयास जारी रखने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान शिक्षक डायरी, मध्यान्ह भोजन योजना, विद्यालय के अभिलेखों तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना की।विद्यालय परिसर में इको क्लब द्वारा विकसित हरियाली और स्वच्छ वातावरण ने सहायक संचालक का विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास केवल परिसर की सुंदरता नहीं बढ़ाते, बल्कि बच्चों के भीतर पर्यावरण संरक्षण, जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का भाव भी विकसित करते हैं। उन्होंने विद्यालय परिवार को इस पहल को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक शैलेंद्र सिंह, पटना संकुल के संकुल प्राचार्य भगवान राम ठाकुर एवं जनशिक्षक रामदयाल सिंह भी उपस्थित रहे। विद्यालय पहुंचने पर प्रधान पाठिका रुक्मणी सिंह एवं विद्यालय परिवार ने अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंटकर आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर विकास कुमार गौतम, किशन लाल कुर्रे, नलिनी कौशिक, सूरज प्रकाश साहू सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।

विश्व विख्यात भजन प्रवाहक कन्हैया मित्तल 18 को सूरजपुर में

*** शहर में गूंजेगा श्याम रस का स्वर, तैयारियों में दिन-रात जुटे श्याम भक्त।**

सूरजपुर/द शूटर। शहर में इन दिनों हर ओर श्याम भक्ति की सुगंध फैलने लगी है। गलियों से लेकर चौक-चौराहों तक श्याम रस का वातावरण महसूस किया जा रहा है। श्री श्याम भक्त मंडल सूरजपुर द्वारा 18 अगस्त को रंगमंच स्थित 25 हजार वर्गफुट के टेनसाईल डोम में आयोजित होने वाले श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव ह्यभरोसाह्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य स्वरूप देने के लिए श्याम भक्त दिन-रात जुटे हुए हैं।

इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि विश्व विख्यात भजन प्रवाहक कन्हैया मित्तल (चंडीगढ़) पहली बार सूरजपुर में बाबा श्याम के भजनों की अमृत वर्षा करेंगे। उनके साथ प्रसिद्ध भजन गायक गौरी शरण (इंदौर) भी अपनी सुरमयी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को श्याम भक्ति में सराबोर करेंगे। आयोजन समिति के अनुसार संकीर्तन की पूरी रात भक्तिमय वातावरण में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति होगी और पूरा नगर बाबा श्याम के जयघोष से गूंज उठेगा।

महोत्सव को सफल बनाने में श्री श्याम भक्त मंडल सूरजपुर के अतुल अग्रवाल, अंकित गर्ग, मुकेश गोयल, शैलेश अग्रवाल, राजू अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, युवराज अग्रवाल, चैतन्य प्रकाश अग्रवाल, गौरांग अग्रवाल, भवीश रोहिला, सचिन गोयल, गौरिश जिंदल, यश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, प्रणव अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, पपल अग्रवाल, संतोष गुप्ता, हरिओम अग्रवाल, उत्पल चट्टोपाध्याय, राकेश कुमार, संस्कार अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, दीपक अग्रवाल सहित श्री श्याम भक्त मंडल के सभी सदस्य एवं आयोजन से जुड़े श्याम प्रेमी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे हुए हैं। समिति ने जिले एवं आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव भरोसा में शामिल होने और बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने की अपील की है।

पूरे नगर में अभी से ही धार्मिक उत्साह की लहर...

समिति के अनुसार पिछले एक महीने से आयोजन की तैयारियां लगातार चल रही हैं। बैठक व्यवस्था, सुरक्षा, पार्किंग, प्रसाद वितरण, जल व्यवस्था और अन्य सभी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित एवं भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। आयोजन के दिन सूरजपुर पूरी तरह श्याममय हो जाएगा और श्रद्धालु देर रात तक संकीर्तन में शामिल होकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

कलकत्ता के कारीगर देंगे दरबार को दिव्य स्वरूप...

बाबा श्याम के दरबार को अलौकिक और आकर्षक स्वरूप देने के लिए कलकत्ता से विशेष दरबार सेवक और फूल सज्जा के कारीगर आमंत्रित किए गए हैं। भव्य पुष्प सज्जा, दिव्य श्रृंगार, इत्र वर्षा और मनमोहक प्रकाश व्यवस्था के साथ बाबा का दरबार श्रद्धालुओं के लिए अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति का केंद्र बनेगा। वहीं श्याम रसोई में हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद एवं भोजन की विशेष व्यवस्था की जा रही है।

मुख्य मांगें मानी गईं, लेकिन संघर्ष अभी बाकी... अपने अधिकारों के लिए राजधानी पहुंची सात विशेष पिछड़ी जनजातियों की बुलंद आवाज

रायपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। राजधानी रायपुर में उस समय सातों विशेष पिछड़ी जनजातियों की एकजुट आवाज का साक्षी बनी, जब प्रदेश के दूरस्थ वनांचलों और पहाड़ी इलाकों से हजारों की संख्या में पहुंचे समाज के लोगों ने शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़े अपने अधिकारों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने साफ कहा कि विकास की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस निर्णय चाहिए।छत्तीसगढ़ सर्व विशेष पिछड़ी जनजाति समाज कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो के नेतृत्व में पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबुझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया और पण्डो समाज के पदाधिकारी एवं अभ्यर्थी प्रदेश के 21 जिलों से रायपुर पहुंचे। इससे पहले 30 जुलाई को सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया था।समाज की प्रमुख मांगों में सहायक शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में पीवीटीजी का अलग विकल्प बहाल करना, टीईटी और डीएलएड में पूर्ववत छूट, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों में 20 प्रतिशत पद विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सुरक्षित करना, पहले से कार्यरत लगभग 400 से 500 सहायक शिक्षकों को विभागीय डीएलएड की सुविधा उपलब्ध कराना, 12वीं में 45 प्रतिशत अंक होने के कारण प्रशिक्षित की मान्यता से वंचित अभ्यर्थियों को राहत देना तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के मरीजों के साथ अस्पतालों में रहने वाले परिजनों को भी निःशुल्क भोजन और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।4 अगस्त को राजधानी में आयोजित प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने पहले कलेक्ट्रेट परिसर में सभा की। विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वर्षों से उपेक्षित विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को रोजगार और शिक्षा में समान अवसर मिलना चाहिए। सभा के बाद जब प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए राजभवन और मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़े तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों ने मांगों को शीघ्र शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया।इसके बाद प्रतिनिधिमंडल मंत्रालय महानदी भवन पहुंचा, जहां शिक्षा मंत्री, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, शिक्षा सचिव, लोक शिक्षण संचालनालय तथा व्यापम के अधिकारियों को अलग-अलग ज्ञापन सौंपे गए।प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार पण्डो ने बताया कि व्यापम कार्यालय में ज्ञापन सौंपते ही अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में पीवीटीजी का विकल्प तत्काल जोड़ दिया, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की तकनीकी परेशानी दूर हो गई। उन्होंने बताया कि समाज द्वारा 30 जुलाई से शुरू किए गए आंदोलन का असर यह हुआ कि 3 अगस्त की शाम राज्य शासन ने सहायक शिक्षक भर्ती में पीवीटीजी अभ्यर्थियों को टीईटी और डीएलएड में पूर्ववत छूट देने तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी आदेश जारी कर दिया।समाज ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांगों पर संवेदनशीलता दिखाई है। साथ ही व्यापम के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने आवेदन प्रक्रिया में पीवीटीजी का विकल्प तत्काल उपलब्ध कराया।

हालांकि समाज का कहना है कि उनकी लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। पूर्व में नियुक्त सैकड़ों सहायक शिक्षकों को विभागीय डीएलएड की सुविधा तथा राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति के मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों को भी निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने जैसी मांगें अब भी अधूरी हैं। इन मांगों को लेकर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।उदय कुमार पण्डो ने कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना किसी प्रकार की कृपा नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। समाज तब तक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा, जब तक सभी लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं हो जाता।इस अवसर पर संरक्षक डॉ. सुखराम दरोपा, प्रवक्ता देवचंद राम पण्डो, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष टीकम नागवंशी भुंजिया, सचिव धनीराम कडमिया, सह सचिव झगरूराम कमार, मीडिया प्रभारी मोहरलाल पण्डो सहित सातों विशेष पिछड़ी जनजातियों के अनेक पदाधिकारी, महिला प्रतिनिधि और युवा अभ्यर्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

अनाथ बच्चों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार का खुलेगा रास्ता

रायपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। जिन बच्चों के सिर से बचपन में ही अपनों का साया उठ जाता है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल परवरिश की नहीं, बल्कि सम्मानजनक भविष्य की होती है। ऐसे ही अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जगाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उनका प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चे केवल संरक्षण तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, कौशल और रोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ें।इसी उद्देश्य से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख श्री विजय एवं कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे से मुलाकात कर बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों को लेकर विस्तृत चर्चा की।बैठक में एक्सिस बैंक के सीएसआर फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, उन्हें रोजगारपरक प्रशिक्षण देने तथा भविष्य में रोजगार से जोड़ने के लिए साझा सहयोग की रूपरेखा पर विचार किया गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को ऐसा अवसर मिलना चाहिए जिससे वह आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ा होकर सम्मानजनक जीवन जी सके।

उन्होंने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के सामाजिक पुनर्वास की यह पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल संचालन हो रहा है और अब इसे राज्य के सभी जिलों तक विस्तार देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र और औद्योगिक घरानों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास करेगी। विशेष रूप से कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, करियर मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सके।बैठक में एक्सिस बैंक के भारत सीएसआर प्रभारी, क्षेत्रीय प्रबंधक, संस्था के संचालक दीपेश, राज्य प्रमुख जिनेश सहित बैंक के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। कुलमिलाकर यह पहल उन बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है, जिनके जीवन में परिस्थितियों ने कठिनाइयां जरूर दी हैं, लेकिन अब उन्हें अपने सपनों को साकार करने का अवसर भी मिलने जा रहा है।

आत्मीय स्वागत के साथ नई उम्मीदों का आगाज, शालेय शिक्षक संघ और नवपदस्थ संयुक्त संचालक के बीच हुआ सकारात्मक संवाद

सूरजपुर/द शूटर। सरगुजा संभाग शिक्षा के नवपदस्थ संयुक्त संचालक डॉ. राजेश कुमार सिंह से शालेय शिक्षक संघ, जिला सूरजपुर के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे के नेतृत्व में सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग का विश्वास व्यक्त किया।

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सूरजपुर जिले के शिक्षकों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक, सेवा संबंधी एवं शैक्षणिक समस्याओं को विस्तारपूर्वक संयुक्त संचालक के समक्ष रखा। शिक्षकों के लंबित प्रकरणों, विद्यालयों की कार्यप्रणाली, शैक्षणिक व्यवस्थाओं तथा शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई।

संयुक्त संचालक डॉ. राजेश कुमार सिंह ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी मामलों का नियमानुसार परीक्षण कर शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के लिए आवश्यक पहल की जाएगी। साथ ही उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका कार्यालय सदैव शिक्षक हित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध रहेगा।

शालेय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष यादवेन्द्र दुबे ने संयुक्त संचालक के सकारात्मक एवं संवेदनशील दृष्टिकोण के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह आत्मीय मुलाकात केवल एक औपचारिक भेंट नहीं, बल्कि सरगुजा संभाग की शिक्षा व्यवस्था एवं सूरजपुर जिले के शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में एक सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाली शुरूआत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संयुक्त संचालक के नेतृत्व में शिक्षकों की लंबित समस्याओं का समयबद्ध निराकरण होगा तथा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में ठोस पहल देखने को मिलेगी।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में जिला सचिव गौतम शर्मा, जिला उपाध्यक्ष संतोष भारती, कोषाध्यक्ष राकेश गौतम, महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अरूणा कौशिक, जिला प्रवक्ता मनीष राय तथा कमल किशोर पाण्डेय, अंकित कोसरिया एवं संजय मिश्रा सहित संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संडे का स्वाद: बढ़िया खाने और सुकून भरे पलों का शानदार अनुभव

संडे ब्रंच बना स्वाद और सुकून का परफेक्ट कॉम्बिनेशन संडे ब्रंच अक्सर मजे और आराम के बीच एक महीन लाइन पर चलते हैं। में एक ब्रंच दोनों देता है, जिसके मेन्यू में ताजे सलाद और शानदार चीज से लेकर पेट भरने वाले मेन कोर्स और शानदार कॉकटेल तक सब कुछ है, यह एक आरामदायक इवेंट है जिसे कुछ देर और खाना चाहिए। दीपांशु एक परफेक्ट होस्ट हैं। खाना कई तरह की ब्रेड, डिप और क्रीम चीज से शुरू होता है। हालांकि फ्लेवर अच्छे हैं, लेकिन क्रीम चीज थोड़ा ज्यादा गाढ़ा लगता है, जिसमें ब्रंच स्प्रेड की शुरूआत में मिलने वाला हवादार टेक्सचर नहीं होता। यह एक मजेदार अनुभव में एक छोटी सी कमी है। पहली बार प्रभात खबर की पहल पर इतिहासकारों ने जोड़े हूल के बिखरे हिस्से टेबल के स्टार्स में से एक, व्हिप्ड फेटा विद कैरामलाइज्ड वॉलनट्स के साथ चीजें जल्दी ही मजेदार हो जाती हैं। क्रीमी फेटा को कैरामलाइज्ड वॉलनट्स के मीठे क्रंच से खूबसूरती से बैलेंस किया गया है, जबकि पैपरिका एक हल्की गर्माहट देती है। हर बाइट में टेक्सचर और फ्लेवर का एक मजेदार मेल मिलता है। जो लोग हल्का खाना चाहते हैं, उनके लिए एडामे क्विनोआ सलाद एक रिफ्रेशिंग ऑप्शन है। एवोकाडो, खीरा और एडामे के साथ, यह साफ, ताजा स्वाद देता है जो धूप वाली दोपहर के ब्रंच के लिए एकदम सही लगता है। चार्ड कॉर्न सलाद एक स्मोकी डायमेंशन जोड़ता है और मेनू के फ्रेश-फॉरवर्ड अप्रोच को पूरा करता है। जिसे उनके चीफ मिक्सोलॉजिस्ट सुप्रदीप ने दुबई से रिकमेंड किया है। उनका दावा है कि यह सोबो20 में संडे ब्रंच का हीरो है। एक क्लासिक वेस्पर मार्टिनी ब्रंच के लिए एकदम सही साथी है – क्रिस्प, एलिगेंट और सोफिस्टिकेटेड, बिना खाने पर हावी हुए। जबकि सलाद, ब्रेड और चीज ग्रेज़िंग टेबल पर हैं, सेट मेनू के दूसरे स्टार आपकी टेबल पर आते हैं। छोटी प्लेटों में एक खास चीज लुइसियाना करी पफ है। तीन-चीज के रिच मिक्स से भरा और मद्रास करी पाउडर से बेहतर, यह कम्फर्ट फूड को मसाले वाले कैरेक्टर के साथ मिलाता है। यह एक ऐसी डिश है जो आते ही टेबल से गायब हो जाती है। स्ट्रैसियाटेला क्रॉस्टिनी सादगी को सेलिब्रेट करती है। यहाँ, क्रीमी चीज बिना किसी शक के हीरो है, जिसका रिच, नाजुक स्वाद दिखाने के लिए क्रिस्प ब्रेड से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यह और ग्रेज़िंग टेबल पर मौजूद बेहतरीन चीज की वैरायटी, मुझे चंदन ब्रूट लेने के लिए लुभाती है। ₹मैं चीज की बुराई नहीं कर सकता,₹ मैंने दीपांश से कहा। वह मुस्कुराया और मेरे फैसले की इज्जत की। स्वीट पोटैटो पो' बॉय इतना जबरदस्त है कि ब्रंच की सबसे ज्यादा भूख भी शांत हो जाएगी। क्रिस्पी शकरकंद, ताजा लेट्यूस और घर का बना क्रियोल केचप एक क्रस्टी बैगेट के अंदर मिलकर एक सैंडविच बनाते हैं जो आसानी से एक कम्प्लीट मील बन सकता है। वेफर टिन केजुन चिकन पिज्जेट सोबो20 संडे ब्रंच में एक और स्वादिष्ट छोटी प्लेट आइटम है। केजुन चिकन, बेल पेपर, प्याज, मोजेरेला सबसे पतले पिज्जा बेस पर फैला हुआ है। समर लेमन टैग्लिओलिनी मेन्यू में गर्मियों वाली चमक लाता है। हल्का और बैलेंस्ड, यह साथ में नींबू के निचोड़ से और भी जानदार हो जाता है, जो स्वाद को बढ़ाता है और एक जानदार सिट्रस किक देता है। और बारटेंडर जयेश चाहते हैं कि मैं न्यू ऑरलियन्स मैरी ट्राई करूँ झ ब्लडी मैरी का क्लैरिफाइड वर्शन। क्लियर और फ्लेवरफुल प्रीबैच्ड ड्रिंक जो मुंह में जान डाल देती है। शेफ चेतन और दीपांश चिली चीज हॉट डॉग्स - मिनी हॉट डॉग, चिली सॉस, चीज, क्रिस्प शैलॉट्स के साथ रिकमेंड करते हैं। चिपचिपा और टेस्टी। हालांकि मुझे सॉसेज थोड़े और पके हुए पसंद आते। मेडिटेरेनियन सॉस में सिट्रस सी बास शायद ब्रंच की सबसे यादगार डिश है। काली मिर्च वाली सॉस के साथ सर्व किया जाता है, जिसमें केपर्स और चेरी टमाटर डाले जाते हैं, यह बहुत अच्छे से पकाया जाता है और बहुत संतोषजनक होता है। एटूफी राइस, जो सब्जियों और फ्लेवर से भरपूर है, चेतन की एक और रिकमेंडेशन है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इसे ट्राई किया। यह स्वादिष्ट और आरामदायक है। मुझे सिर्फ इसके लिए वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डेजर्ट! खैर, सोबो20 का फेमस चॉकलेट पाटे जो शेफ खुद सर्व करते हैं, उसे मिस नहीं करना चाहिए।

सरला भट मामला: यद्यपि विलंबित, न्याय की आशा की किरण

यद्यपि विलंबित, न्याय की आशा की किरण 1990 में सरकारी नर्स सरला भट की हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) द्वारा 737 पेज का आरोपपत्र दाखिल करना एक अनुस्मारक है कि न्याय, हालांकि दर्दनाक रूप से धीमा है, उसे स्थायी रूप से अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मामले को इस स्तर तक लाने में जांचकताओं को 36 साल लग गए। देरी असाधारण है, लेकिन यह तथ्य कि कानून ने आखिरकार कश्मीर के सबसे काले अपराधों में से एक को पकड़ लिया है, उन सभी को आश्वासन देता है जो कानून के शासन में विश्वास करते हैं। जिस दृढ़ता की मांग की गई उसके लिए जांच की सराहना की जानी चाहिए। तीन दशक से अधिक समय के बाद किसी हत्या का पुनर्निर्माण करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। गवाह बूढ़े हो गए थे, कई 70 वर्ष की आयु पार कर रहे थे, जबकि कुछ गवाही देने से पहले ही मर गए थे। यादें धुंधली हो गई थीं, रिकॉर्ड्स को पुनः प्राप्त करना पड़ा, और फोरेंसिक के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी कड़ी मेहनत से इकट्ठा करना पड़ा। जिन अधिकारियों ने एक ऐसे मामले को पुनर्जीवित किया जो दशकों से निष्क्रिय पड़ा हुआ था, वे उस मामले को जोड़ने के लिए श्रेय के पात्र हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह एक निर्विवाद मामला है। ही सच्ची परीक्षा होगी हालाँकि, सच्ची परीक्षा आगे है। आरोप पत्र दाखिल करना एक बात है; दोषसिद्धि सुनिश्चित करना बिल्कुल दूसरी बात है। प्रत्येक आरोप को कठोर न्यायिक जांच और जिरह का सामना करना होगा। केवल निष्पक्ष सुनवाई ही आरोपी के अपराध का निर्धारण कर सकती है। फिर भी, यदि जांच ने वास्तव में सबूतों की एक अटूट श्रृंखला स्थापित की है, तो अभियोजन पक्ष के पास आश्वस्त होने का हर कारण है। सरला भट्ट की कहानी जांच को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे समय में जब आतंकवाद ने घाटी को अपनी चपेट में ले लिया था और डर ने कई कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था, उन्होंने शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक नर्स के रूप में अपने पद पर बने रहने का फैसला किया। बार-बार धमकियों के बावजूद, चाहे उसके मरीज कोई भी हों, उसने अपना पेशेवर कर्तव्य निभाना जारी रखा। आरोप पत्र के अनुसार, यह आरोप कि उसने पुलिस मुखबिर के रूप में काम किया,

पहली बार प्रभात खबर की पहल पर इतिहासकारों ने जोड़े हूल के बिखरे हिस्से

इतिहासकारों ने जोड़े हूल के बिखरे हिस्से बरहेट के छोटे-से गांव भोगनाडीह की तरफ चारों दिशाओं से लोग चले आ रहे थे. किसी के कंधे पर तीर-धनुष था, किसी के हाथ में फरसा, तो किसी की कमर से कुल्हाड़ी बंधी थी. हजारों कदमों की धूल हवा में उड़ रही थी. जंगल के रास्तों पर नगाड़ों की धीमी थाप सुनाई दे रही थी, पर आज का दिन उत्सव का उल्लास नहीं, बल्कि भीतर सुलगते गुस्से की गूंज थी. कुछ ही देर में गांव के मैदान में 10 हजार से अधिक संताल जमा हो गये. बूढ़े, जवान, महिलाएं, मांझी, परगनैत- हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था- अब और कब तक? मैदान के बीचोंबीच सिदो और कान्हू खड़े थे. उनके साथ चांद, भैरव, फूलो और झानो भी थे. सिदो ने चारों ओर नजर दौड़ायी. जहां तक नजर जाती, अपने ही लोग दिखायी दे रहे थे, जिनके चेहरों पर वर्षों का अपमान, भूख और अन्याय साफ झलक रही थी. सन्नाटे के बीच सिदो ने ऊंची आवाज में कहा- ह्यनितोक दो. खाजना बाबोन एमा आर ओकोयाक गोबोलरे हों. बाबोन ताहेना. तेहेञ खोन माहाजोन, दोरोगा आर पोण्ड हारताकोआक हुकुम बाङ चालाक्आ. आबोआक दिसोमरे आबोवाक राज होयोक्आ. नोआ मुंहिन खोन बाञ्चावोक लागित ते हूलगे आबोआक मुचात सापाप् काना. जिवेदोक चाहेबोन गुजुक, लाड़हाईकातेगे दिसोमबोन रूखिया दाड़ेयाक्आ. तेहेञ खोनगे आक सार बोझायपे, कापी तारवाड़े गासाव लासेरपे आर हूल लागित पाठे केटेजोक पे. ओनकोआक नास होयोक्आ आर आबोआक जीत होयोक्आ. संदेह में बदल गयी है हमारी नागरिकता सिदो के भाषण का हिंदी रूपांतरण (अब हम लगान नहीं देंगे और किसी के गुलाम नहीं बनेंगे. आज महाजन, दारोगा और गोरी चमड़ी का हुक्म नहीं चलेगा. हमारे देश में हमारा राज होगा. इस मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए हूल ही हमारा आखिरी हथियार है. हम जियें या मरें, लड़कर ही अपनी आजादी को बचा पायेंगे. आज से तीर-धनुष तैयार करो, तलवार-फरसा तेज करो और हूल के लिए कमर कस लो. उनका नाश होगा और हमारी जीत होगी.) इसके बाद भीड़ में जैसे बिजली दौड़ गयी. हजारों धनुष एक साथ आसमान की ओर उठे. आवाज गूंजी हूंकार से कांपी राजमहल की पहाड़ियां राजमहल की पहाड़ियां इस हुंकार से कांप उठीं, लेकिन यह गुस्सा एक दिन में नहीं पैदा हुआ था. यह उन जख्मों की आग थी, जो वर्षों से भीतर सुलग रही थी. सिदो ने सभा में उपस्थित लोगों से कहा- आज बोलो. जो तुम्हारे साथ हुआ, सबके सामने कहो. सबसे पहले एक बूढ़ा किसान उठा. उसकी आंखें धंसी हुई थीं. बूढ़े किसान ने कहा- मैंने जंगल काटाङ्क खेत तैयार कियेङ्क पांच साल तक जी तोड़ मेहनत की. अब महाजन कहता है- यह जमीन उसकी है. यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया. एक दूसरी आवाज आयी- ह्यमेरी पूरी फसल ले गया फिर भी कहता है- कर्ज बाकी है. तीसरा आदमी उठा, गुस्से में कहा- दारोगा कहता है- जेल भेज दूंगा.

फिर एक महिला खड़ी हुई. उसकी आवाज कांप रही थी. ह्यहमारे घर में घुस आये थे मुर्गियां उठा ले गये विरोध किया तो कहा- चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे आदमी को जेल भेज देंगे. अब हर तरफ से आवाजें आने लगीं. हमारी जमीन, हमारा अनाज, हमारी बेटियां, हमारी इज्जत ऐसा लग रहा था, मानो वर्षों से दबा हुआ दर्द आज पहली बार शब्द बनकर बाहर निकल रहा हो. सिदो सब सुनते रहे. फिर धीरे से बोले-याद करो यह सब कब शुरू हुआ था? और यहीं से मानो पूरा मैदान वर्षों पहले अतीत में लौट गया राजमहल की पहाड़ियों में घने जंगल थे, जिसमें मालेर जनजाति के लोग रहते थे. उनका जीवन बेहद ही साधारण था और जंगल के उत्पादों के भरोसे उनकी जिंदगी चलती थी. फिर समय बदला.

1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली. उस समय वर्तमान झारखंड का अधिकांश भाग बंगाल प्रांत के ही अधीन था, इसलिए यहां भी राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के हाथों में आ गया. कंपनी का उद्देश्य साफ था- ज्यादा से ज्यादा राजस्व कमाना. पर इन पहाड़ियों में रहने वाले मालेरों (माल पहाड़िया) से कर वसूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वे स्थायी खेती नहीं करते थे. संताल विद्रोहियों की तालश करती अंग्रेजो की सेना` तस्वीर वॉल्टर शेरवित द्वारा बनायी गयी है उधर, बंगाल की धरती पर हालात तेजी से बदल रहे थे. 1772 में तत्कालीन गर्वनर वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा लागू की. एक गांव का किसान अपने बेटे से कह रहा था- अब जमीन हमारी नहीं रही बेटाङ्क जो सबसे ज्यादा बोली लगायेगा, वही हमारा मालिक होगा. बेटे ने पूछा- ह्यफिर हम क्या करेंगे? बूढ़े ने आह भरते हुए कहा- ह्यकर देंगे नहीं दिया तो खेत चला जायेगा. इजारेदारों ने किसानों से मनमाना कर वसूलना शुरू कर दिया. फिर 1793 में गर्वनर लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया. अब जमींदार भूमि के स्वामी बना दिये गये.

संदेह में बदल गयी है हमारी नागरिकता

नागरिकता आजादी के 79 साल बाद, हर बार झंडा फहराते हुए आत्मविश्वासी भारतीय गणराज्य के वादों के बाद भी, हर भारतीय को राष्ट्र से जोड़ने वाली अटूट कड़ी के रूप में बेची गयी डिजिटल पहचान पर अरबों खर्च करने के बाद भी, भारतीय आज तक ऐसे दस्तावेजों को पकड़े हुए हैं, जिन्हें अब खुद सरकार ही बारिश में भीगते कागज के टुकड़ों जैसा मानती है. एक साल पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आरोपी घुसपैठिए को जमानत देने से इनकार करते हुए साफ कहा था कि आधार, पैन और वोटर आइडी नागरिकता साबित नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट ने समानांतर कार्यवाही में आधार के बारे में यही कठोर सच्चाई दोहरायी.सरकार यहीं से पीड़ा शुरू हुई. अगर पहचान के ये प्रतीक कानूनी जांच में ढह जाते हैं, तो फिर उस भारत का क्या बचता है, जिसका हिस्सा होने का भारतीयों ने विश्वास किया था? इस घाव को विदेश मंत्रालय ने अब और गहरा कर दिया है. पासपोर्ट सेवा दिवस पर उसने घोषणा की कि भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है और नागरिकता के प्रमाण के रूप में इसका कोई निर्णायक महत्व नहीं है. उस मंत्रालय ने, जो पासपोर्ट अधिनियम के तहत यह दस्तावेज जारी करता है, इसे सार्वजनिक रूप से नागरिकता से अलग कर दिया है. पीड़ा इसलिए और गहरी हो जाती है, क्योंकि इसका अनुभव उन तमाम लोगों

को हो रहा, जिन्होंने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर कतार लगायी, बायोमीट्रिक दिया और यह विश्वास लेकर बाहर निकला कि नीली किताब उसके राष्ट्र में निश्चित जगह की पुष्टि करती है. अ'रङ्क र्फी - पहली बार प्रभात खबर की पहल पर इतिहासकारों ने जोड़े हूल के बिखरे हिस्से पासपोर्ट अधिनियम की प्रस्तावना भी साफ कहती है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को दिया जायेगा. फिर भी अब विदेश मंत्रालय आम भारतीयों से कह रहा है कि उनका पासपोर्ट उनके बारे में कुछ भी साबित नहीं करता. यह कानून का विकास नहीं है. यह उसी विश्वासघात का विस्तार है, जिसे अदालतों ने एक साल पहले उजागर किया था. पहले प्लास्टिक और डिजिटल पहचान को अर्थहीन बना दिया गया. अब भारत के सबसे गंभीर यात्रा दस्तावेज को भी उसी खोखले प्रमाणों की सूची में जोड़ दिया गया है. यह यातना केवल सैद्धांतिक नहीं है. यह उन परिवारों की शांत घबराहट में दिखती है, जिनकी जड़ें विभाजन से पहले के भारत तक जाती हैं, जिनके कागज समय के साथ खो गये, और जो अब सोचते हैं कि क्या पिछले साल नवीनीकृत किया गया उनका पासपोर्ट भी अगली जांच में टिक पायेगा.

विरोधाभास अदालत की किसी भी टिप्पणी से अधिक गहरे हैं. जब यही विदेश मंत्रालय विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिशन प्रमुख नियुक्त करता है, तब वह उन्हें सेवा रिकॉर्ड और उसी पासपोर्ट के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट देता है, जिसे वह अब खारिज कर रहा है. विदेशी सरकारें बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के इन प्रमाणपत्रों को स्वीकार करती हैं. संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अपने नामांकन पत्रों के माध्यम से नागरिकता घोषित करते हैं, जो मुख्य रूप से मतदाता पंजीकरण प्रमाणपत्रों पर आधारित होते हैं. कोई अलग नागरिकता प्रमाणपत्र न तो मांगा जाता है और न ही पेश किया जाता है. अगर पासपोर्ट और वोटर आइडी किसी की भारतीयता साबित नहीं कर सकते हैं, तो ये प्रतिनिधि देश के लिए बोलने या कानून बनाने के योग्य कैसे हैं? राज्य शासकों को चुपचाप मान्यता देता है, जबकि शासितों से लगातार कठिन प्रमाण मांगता है. यह असमानता आम नागरिकों को असुरक्षित छोड़ती है और राजनीतिक वर्ग को बचाती है. संकट हर चतुर्थी और कर्म और बुद्धि का मार्ग राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस विभाजन को और तेज कर दिया है. विपक्षी नेताओं ने विदेश मंत्रालय के बयान को जानबूझकर भ्रम पैदा करने का प्रमाण बताया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे ह्यहर भारतीय के खिलाफ संदेह का माहौल बनानेह्ल की कोशिश कहा, ताकि सरकार मतदाता सूची से नाम हटाने को उचित ठहरा सके. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक ह्यखतरनाक खेलह्ल बताया, जो पीढ़ियों से यहां रहने वाले नागरिकों की पहचान पर सवाल उठाता है. इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं ने भी यही कहा. बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची संशोधन के दौरान विपक्ष ने जब चुनाव आयोग की सख्ती की आलोचना की थी, तब सरकार और भाजपा के नेताओं ने उसका कड़ा विरोध करते हुए कहा था कि यह कोई नयी बात नहीं है. आंकड़े भ्रम की व्यापकता दिखाते हैं. लगभग 2.5 फीसदी भारतीयों के पास ही पासपोर्ट है. सरकार ने आधार बनाने में 12,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये, और यह बैंकिंग, कर और यात्रा के लिए अनिवार्य है. फिर भी जब नागरिकता की बात आती है, तो इसे अप्रासंगिक बता दिया जाता है.

चीन कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में अपना विस्तार कर रहा है?

भारतीय उपमहाद्वीप में अपना विस्तार सुमदोरोंग चू घटना के चालीस साल बाद, खबर है कि उत्तर-मध्य अरुणाचल प्रदेश में एक छोटी जनजाति ने शिकायत की है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने उसकी पारंपरिक चारागाह भूमि में अतिक्रमण किया है और वहां संरचनाओं का निर्माण किया है, जिससे डेजा वु की भावना आती है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्वदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन नाह वेलफेयर सोसाइटी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) पर सुबनसिरी नदी के उत्तर में ताकसिंग के पास पारंपरिक चरागाह और शिकार क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने का आरोप लगाया है। स्थानीय अधिकारियों को सौंपे गए अभ्यावेदन में, समूह ने आरोप लगाया है कि चीनी सेना ने उस क्षेत्र में सड़कों, पुलों और सैन्य शिविरों का निर्माण किया है, जो स्थानीय निवासियों का कहना है कि हाल के वर्षों तक उनके लिए सुलभ था, इस चिंता को रेखांकित करता है कि बीजिंग जमीन पर बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से विवादित सीमांत क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। निःसंदेह, ऐसे दावों को हमेशा कुछ हद तक सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए। वास्तविक नियंत्रण रेखा कई क्षेत्रों में विवादास्पद और अस्पष्ट रूप से परिभाषित बनी हुई है। पारंपरिक चरागाह सीमाओं के बारे में सामुदायिक धारणाएँ हमेशा आधिकारिक मानचित्रों या सैन्य मानचित्रण के अनुरूप नहीं होती हैं। चीनी घुसपैठ के कुछ पिछले आरोप बाद में अतिरंजित साबित हुए हैं। इतिहासकारों ने जोड़े हूल के बिखरे हिस्से हालाँकि, सुमदोरोंग चू सहित अन्य, बीजिंग द्वारा विवादित क्षेत्र की जाँच के वास्तविक उदाहरण थे। यह संकट तब सामने आया जब 1986 में सुमदोरोंग चू के चरागाहों पर पीएलए द्वारा कब्जा किए जाने की खबरें आईं, जो शिक्षाप्रद बना हुआ है। सीमा गतिशीलता बदलना 1986 में, राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के दो साल से भी कम समय के बाद, भारत ने उच्च हिमालय में सैनिकों और तोपखाने की तेजी से एयरलिफ्ट के साथ चीनी अग्रिम आंदोलन का जवाब दिया, इसके बाद 1987 में ऑपरेशन चेकरबोर्ड किया गया। जनरल के सुंदरजी द्वारा आदेशित इस कदम ने सैन्य संकल्प के साथ चीनी जबरदस्ती का मुकाबला करने की भारत की इच्छा को रेखांकित किया। रणनीतिक संतुलन काफी बदल गया है। चीन ने तिब्बती पठार में बुनियादी ढांचे का नाटकीय रूप से विस्तार किया है, सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़कें, पुल, हवाई क्षेत्र, सैन्य चौकियां, हेलीपैड और दोहरे उपयोग वाले सीमावर्ती गांवों का निर्माण किया है। यह बुनियादी ढांचा बीजिंग को विवादित क्षेत्रों में अधिक बार गश्त करने और तेजी से सेना जुटाने की अनुमति देता है, जिससे भारत की प्रतिक्रिया खिड़की संकुचित हो जाती है।

शायरी से आगे बढ़ी डॉ. आबिद मोईज की सोच, उर्दू की नई संभावनाओं पर जोर

उर्दू सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं, डॉ. आबिद मोईज ने बताई भाषा की व्यापक क्षमता क्या उर्दू सिर्फ. शायरी, गजल, मुशायरे, गालिब, इकबाल और फैज के बारे में है? कई लोगों को इसका जवाब जोरदार हाँ लगता है। उर्दू को अक्सर नज्मों, रोमांटिक दोहों और दिल को छू लेने वाले गानों से जोड़ा जाता है। यह भाषा मुशायरों में ज़िंदा हो उठती है जहाँ दर्शक हर लाइन पर झूमते हैं और शायरों को जोरदार तालियों से इनाम देते हैं। एक मशहूर कहावत है, जहाँ उर्दू, वहाँ शायरी। लेकिन क्या शायरी ही उर्दू की अकेली पहचान है? क्या यह भाषा साइंस, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न नॉलेज का जरिया भी बन सकती है? डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, राइटर और स्कॉलर डॉ. आबिद मोइज का मानना है कि ऐसा हो सकता है। अपनी बहुत सारी राइटिंग के जरिए, उन्होंने लगातार यह दिखाया है कि उर्दू में सिर्फ. इमोशंस ही नहीं, बल्कि आइडिया, डिस्कवरी और साइंटिफिक नॉलेज को भी बताने की काबिलियत है। डॉ. मोइज उर्दू को शायरी की जंजीरों से आजाद करना चाहते हैं। काम में इजाफा हेल्थ, मेडिसिन, साइंस, ह्यूमर और भाषा पर 40 से ज्यादा किताबें लिखने वाले डॉ. मोइज, अदीब और तबीब का एक अनोखा मेल दिखाते हैं झ एक लेखक और एक मेडिसिन के जानकार। डॉक्टर बनने से बहुत पहले ही, उन्हें उर्दू लिटरेचर से गहरा लगाव हो गया था। दशकों से उन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन और अपने लिटरेचर के जुनून के बीच कामयाबी से बैलेंस बनाया है। हाल ही में, डॉ. मोइज ने अपने शानदार काम में दो और किताबें जोड़ीं – शायरी जरिया-ए-इज्जत नहीं और इस्तेलाहातः बोझिए और बनाइए। इन किताबों के साथ, वह आधी सदी पूरी करने से सिर्फ. एक किताब पीछे हैं, जो किसी ऐसे इंसान के लिए एक बड़ी कामयाबी है जो उर्दू को सिर्फ. शायरी की दुनिया तक सीमित नहीं रखना चाहता। उर्दू लिटरेचर में शायरी का बेशक एक बड़ा नाम है। फिर भी, डॉ. मोइज को लगता है कि यह भाषा शायरी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कई लिटरेचर सर्कल में, किसी इंसान को तभी जानकार माना जाता है जब वह हर मौके के लिए सही दोहे सुना सके। उनके शब्दों में, कविता को कोट करने की काबिलियत उर्दू स्कॉलरशिप की एक कसौटी बन गई है। भाषा को बेहतर बनाती है, लेकिन यह उसकी अकेली पहचान नहीं बननी चाहिए। उनका कहना है कि उर्दू, मेडिसिन, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और एजुकेशन से जुड़ा लिटरेचर भी उतनी ही काबिल है। उनकी किताब 'शायरी जरिया-ए-इज्जत नहीं' का टाइटल मिर्जा गालिब के मशहूर शेर से लिया गया हैः डॉ. मोइज इस मशहूर शेर का इस्तेमाल इस आम सोच को चुनौती देने के लिए करते हैं कि उर्दू में पहचान सिर्फ.कविता से ही मिल सकती है। उनके मुताबिक, मेडिसिन, साइंस, रिसर्च, ट्रांसलेशन और स्कॉलरशिप में बेहतरीन काम बराबर सम्मान के लायक हैं। प्यार भरा, कठोर नहीं इस किताब में सऊदी अरब में उनके रहने के दौरान लिखे गए कई लेख हैं, जहाँ उन्होंने लिटरेरी एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लिया और वीकेंड पर मुशायरे ऑर्गनाइज किए। जहाँ उन्हें कविता और कविता की महफि लें पसंद थीं, वहीं उन्होंने लिटरेरी कल्चर की ज्यादतियों को भी देखा। ह्यूमर और सटायर के जरिए, वह कुछ कवियों के घमंड, दिखावे और अजीब आदतों को धीरे से सामने लाते हैं। वजन संभाल के,दाद तालाब और अर्ज किया है जैसे आर्टिकल मजाक और ह्यूमर से भरे हैं। डॉ. मोइज अपने तरीके को चेदख्वानी कहते हैं झ मजाकिया टीज़िंग। उनका सटायर कठोर नहीं बल्कि प्यार भरा है, जिससे पढ़ने वालों को लिटरेरी सर्कल की अजीब बातों पर हंसी आती है। उनकी दूसरी किताब, इस्तेलाहातः बोझिए और बनाइए, एक ज्यादा गंभीर मुद्दे पर बात करती हैः उर्दू में साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट। मॉडर्न ज़िंदगी में साइंस और टेक्नोलॉजी का दबदबा है। नई खोजें और इन्वेंशन लगातार नए कॉन्सेप्ट और वोकैबुलरी लाते रहते हैं। भाषाएँ तभी ज़िंदा रहती हैं और बढ़ती हैं जब वे इन बदलावों को अपना सकती हैं। इंग्लिश ने साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को डेवलप और स्टैंडर्डाइज करने में बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उर्दू इसके साथ चलने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तकनीकी शब्दावली का कम विकास एक चिकित्सक, पोषण विशेषज्ञ और लेखक के रूप में चार दशकों से अधिक के अनुभव का लाभ उठाते हुए, डॉ. मोइज शिक्षा और संचार में शब्दावली के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि उर्दू-माध्यम की शिक्षा में गिरावट और रोजगार के सीमित अवसरों ने भाषा में तकनीकी शब्दावली के विकास को हतोत्साहित किया है। साथ ही, कंप्यूटर, इंटरनेट और टेलीविजन जैसे कई अंग्रेजी शब्द इतने व्यापक रूप से स्वीकृत हो गए हैं कि उन्हें उर्दू समकक्षों से बदलना न तो व्यावहारिक हो सकता है और न ही वांछनीय। उनके अनुसार भाषाओं को लचीला रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उपयोगी शब्दों को अपनाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि उर्दू में वैज्ञानिक शब्दावली का अभाव है। वास्तव में, अनेक शब्द पहले से ही मौजूद हैं।

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भारत के खिलाफ बांग्लादेश में भारी गुस्सा

बांग्लादेश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में सीधे मीडिया से बातचीत की अनुमति दिए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है.बांग्लादेश सरकार ने कहा, ₹उस कार्यक्रम के जरिए शेख हसीना और उनके सहयोगियों ने बांग्लादेशी राज्य और देश के लोगों का मजाक उड़ाया है.₹

इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाकिब अल हसन के देखे जाने के बाद उनके घर पर बुधवार रात हमले का दावा किया जा रहा है. बांग्लादेश अवामी लीग ने एक्स पर बयान जारी किया है, ₹बांग्लादेश के मशहूर क्रिकेट आइकन शाकिब अल हसन के आवास पर पेट्रोल बम से एक भयावह हमला हुआ. यह हमला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें विश्व प्रसिद्ध स्टार क्रिकेटर ने सम्मानित पार्टी अध्यक्ष शेख हसीना के साथ हिस्सा लिया था. अवामी लीग के बयान में कहा गया है, ₹प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी रिपोर्टें प्रकाशित कीं तो उनके खिलाफ न्यायपालिका का इस्तेमाल कर मुकदमे दायर किए जाएंगे.

अवामी लीग ने इस हमले को कथित लोकतंत्र निर्माण के नाम पर पार्टी कार्यकताओं के खिलाफ जारी कथित जनसंहार अभियान का एक और उदाहरण बताया और फासीवाद करार दिया है.बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. वह पांच अगस्त 2024 को सत्ता से हटाए जाने के बाद से ही भारत में हैं.हालांकि, पिछले दो सालों में यह पहली बार है जब उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सीधे पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया.बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ₹सरकार ने पहले ही इस कार्यक्रम के बांग्लादेश-भारत द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्माण पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई थी. इसके बावजूद, ढाका ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति दिए जाने पर गहरा खेद जाहिर करता है.₹

बुधवार शाम शेख हसीना ने दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअली संबोधित किया.उन्होंने फिर एलान किया कि वह बांग्लादेश लौटेंगी. उन्होंने कहा कि वह दिसंबर तक लौटेंगी, लेकिन कोई तय तारीख नहीं बताई.इसके कुछ ही समय बाद रात करीब 11 बजे बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के फेसबुक पेज पर एक बयान जारी किया गया.बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, ₹भारतीय धरती पर शेख हसीना का प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन हुआ जब बांग्लादेश की जनता जुलाई क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रही है. यह बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला है और जुलाई क्रांति के शहीदों का अपमान है.बयान में आगे कहा गया, इस देश की जनता ने जुलाई क्रांति की भावना को अपनाते हुए दृढ़ संकल्प लिया है कि हमारा राष्ट्र कभी भी फासीवाद के उन अंधेरे दिनों में वापस नहीं जाएगा और बांग्लादेश कभी किसी का वफादार या संरक्षित राज्य नहीं बनेगा. जनसंहार की दोषी (शेख) हसीना और उनका माफिया गिरोह अब कभी बांग्लादेश की राजनीति में जगह नहीं पाएगा.बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश संप्रभुता, समानता, पारस्परिक सम्मान, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देने और राष्ट्रीय गरिमा के आधार पर भारत के साथ रचनात्मक, पारस्परिक रूप से लाभकारी और भविष्य की ओर देखने वाले संबंध बनाए रखना चाहता है.बयान में शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भी निराशा जाहिर की गई है.इसमें कहा गया है, अफसोस की बात है कि बांग्लादेश और भारत के बीच 2013 में हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत दोषी अपराधी (शेख) हसीना को वापस भेजने के लिए बांग्लादेश की ओर से बार-बार किए गए अनुरोधों पर भारत सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.इसके उलट, किसी भी बहाने से उन्हें सार्वजनिक रूप से मीडिया से बातचीत का अवसर देना इस देश के लोगों की भावनाओं को आहत करता है और बांग्लादेश और भारत के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण के लिए बेहद नुकसानदेह है.

रणधीर जायसवाल

इससे पहले बीते मंगलवार को पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया मांगी थी.उनसे पूछा गया था कि बुधवार को शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारत का क्या रुख है, जिसको लेकर बांग्लादेश पहले ही चिंता जता चुका है.जवाब में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ₹उस कार्यक्रम का आयोजन एक निजी संस्था कर रही है. भारत सरकार का उससे कोई संबंध नहीं है. वहां व्यक्त किए गए किसी भी विचार या बयान का समर्थन भारत सरकार नहीं करती और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है.₹

गॉल ब्लैडर में पथरी कैसे बनती है, इसका पता कैसे चलता है और इलाज क्या है?

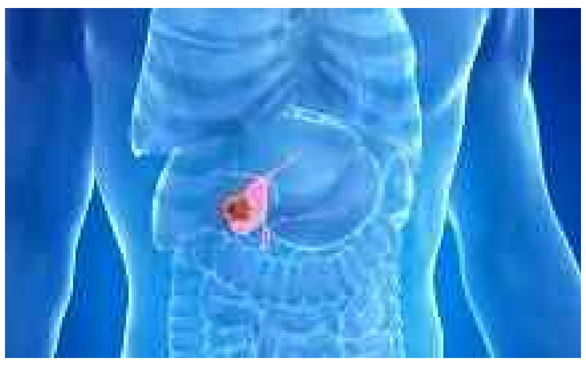

अचानक मेरे पेट के दाहिने हिस्से में बहुत तेज दर्द होने लगा. मुझे लगा कि यह गैस की वजह से होगा. दवा लेने के बावजूद दर्द कम नहीं हुआ. आखिरकार जांच करवाने पर पता चला कि मुझे पित्ताशय (गॉल ब्लैडर) की पथरी है.कई लोग इस तरह का अनुभव साझा करते हैं.गॉल ब्लैडर की पथरी (स्टोन) दुनिया भर में पाई जाने वाली पाचन तंत्र से संबंधित एक आम बीमारी है.इससे पीड़ित कई लोगों में वर्षों तक कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों में यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे तेज दर्द, संक्रमण, जॉन्डिस और में सूजन. यदि समय रहते इसकी पहचान और सही उपचार कर लिया जाए, तो इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है इसका मुख्य काम लिवर द्वारा प्रतिदिन बनाए जाने वाले बाइल (पित्त) को अस्थायी रूप से इकट्ठा करना होता है.

2. गॉल ब्लैडर में पथरी कैसे बनती है?जब इन तीनों तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो छोटे-छोटे क्रिस्टल बनने लगते हैं. समय के साथ ये क्रिस्टल बड़े होकर पथरी का रूप ले लेते हैं.

गॉल ब्लैडर में पथरी बनने की वजह-

पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना

गॉल ब्लैडर का पूरी तरह से खाली न हो पाना

बिलीरुबिन का अत्यधिक उत्पादन होना

गॉल ब्लैडर में संक्रमण या सूजन होना

3. गॉल ब्लैडर की पथरी कितने प्रकार की होती है?

1. कोलेस्ट्रॉल की पथरी

इस प्रकार की पथरी सबसे आम होती है, जो लगभग 80 प्रतिशत मामलों में बनती है.

2. पिगमेंट पथरी

यह बिलीरुबिन का स्तर बढ़ने के कारण बनती है. यह आमतौर पर लिवर की बीमारियों या कुछ खून से संबंधित बीमारियों में विकसित होती है.

3. मिश्रित पथरी

यह कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और बिलीरुबिन के मिश्रण से बनती है.

4. सबसे अधिक खतरा किसे होता है?

डॉक्टर 5ऋफॉमूर्ला को याद रखते हैं-

फीमेलः महिलाओं में यह समस्या अधिक होती है

फोर्टीः 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग

फैट : शरीर का अधिक वजन

फर्टाइलः ऐसी महिला जो गर्भवती हो सकती है

फेयरः पश्चिमी देशों में रहने वाले गोरी त्वचा वाले लोग

5. अन्य जोखिम कारक क्या हैं?

मोटापा

शुगर

हाई कोलेस्ट्रॉल

गर्भावस्था

एस्ट्रोजन हार्मोन की दवाइयाँ

परिवार में पहले किसी को गॉल ब्लैडर की पथरी होना

लंबे समय तक व्रत रखना या भूखे रहना

तेजी से वजन कम होना

बहुत अधिक वसा वाला भोजन

कम फाइबर वाला भोजन

लिवर की बीमारियाँ

हीमोलिटिक एनीमिया

अचानक शराब छोड़ने के बाद क्या होता है, हर रोज कितनी मात्रा में शराब पीना सुरक्षित है?

हर किस्म के नशे से मुक्त रहना अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. सभी नशों का सेहत पर बुरा असर पड़ता है लेकिन शराब के शारीरिक दुष्प्रभाव कहीं अधिक चौंकाने वाले हैं.शराब पर नए शोध सामने आए हैं और इन्हें नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.डॉक्टरों के मुताबिक, शराब का सेवन चाहे कभी-कभार किया जाए या रोजाना, यह शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है.इस लेख में शराब के शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभावों और अचानक शराब पीना बंद करने के परिणामों पर चर्चा की गई है.कई लोगों का मानना है कि वे जो शराब पीते हैं, वह सीधे उनके पेट में जाती है और फिर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है. हालांकि, अधिकांश लोग शरीर के विभिन्न अंगों पर शराब के प्रभावों से अनजान होते हैं.हमने एमजीएम हेल्थकेयर के किडनी प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉ. त्यागराजन से इस बारे में बात की.उन्होंने कहा, ₹इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मात्रा में, कितनी बार या कितने समय तक शराब पीते हैं, लेकिन यह सच है कि शराब शरीर के लिए हानिकारक है. इसके अलावा, महिलाएँ पुरुषों की तुलना में शराब के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं. वे इससे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती हैं.शरीर में अल्कोहल की यात्रा के बारे में डॉ. त्यागराजन कहते हैं, ₹अल्कोहल सीधे पेट से छोटी आंत में जाता है. वहाँ अल्कोहल एल्डिहाइड नामक रसायन में टूट जाता है.₹पेट और आंतों से सारा रक्त लिवर से होकर शरीर के बाकी हिस्सों तक जाता है. लिवर का काम भोजन से पोषक तत्वों को अलग करना और उन्हें खून के माध्यम से शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाना है, और मूत्र व मल के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट और अशुद्धियों को बाहर निकालना है.डॉ. त्यागराजन कहते हैं, ₹एल्डिहाइड एक खतरनाक पदार्थ है. यह रक्त के माध्यम से लिवर तक पहुँचता है और लिवर को नुकसान पहुँचाता है. इसलिए, जब आप कम समय में बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो शरीर में एल्डिहाइड की मात्रा बढ़ जाती है और इससे लिवर काम करना बंद कर देता है.शराब का असर पुरुषों और महिलाओं दोनों पर पड़ सकता है. हालांकि, महिलाओं के मामले में डॉ. त्यागराजन का कहना है कि आनुवंशिक संरचना के कारण महिलाएँ शराब के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं.वो कहते हैं, ₹लगातार शराब पीने से लिवर में खतरनाक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और लिवर में निशान पड़ जाते हैं, जिससे उसे नुकसान पहुँचता है. इससे फाइब्रोसिस हो सकता है. इसका मतलब है कि लिवर में निशान पड़ जाते हैं, वहाँ की कोशिकाएँ मोटी हो जाती हैं और उनकी लोच कम हो जाती है.₹इसके साथ ही अन्य कारक लिवर सिरोसिस का कारण बनते हैं. इसका मतलब है कि लिवर की अच्छी कोशिकाएँ निशान वाली, मोटी कोशिकाओं से बदल जाती हैं.₹

पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग पर लगाई गई पाबंदियों की हो रही आलोचना

पाकिस्तान ने देश में इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग पर नई पाबंदियां लगाई हैं. इस कदम की पत्रकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है.अब विदेशी मीडिया के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को, जिसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के अलावा किसी भी जगह से रिपोर्टिंग करने के लिए इजाजत लेनी होगी.इन पाबंदियों के कारण पाकिस्तान के ज्यादातर हिस्सों में विदेशी मीडिया की ग्राउंड रिपोर्टिंग अधिकारियों की मजी और समय पर निर्भर हो जाएगी. पाकिस्तान अभी 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' में 180 देशों में से 153वें स्थान पर है.पॉलिटिकल कमेंटेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, ₹ये गाइडलाइंस इंटरनेशनल मीडिया के लिए काम करने की जगह को और तंग करते हुए उसका गला घोंटने जैसा है.मीडिया पर पाबंदियां कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के मुकाबले लोकल मीडिया पर अक्सर ज्यादा दबाव होता है.खोखर कहते हैं, ₹लोग निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल मीडिया पर भरोसा करते हैं.पाबंदियां लगाने से सिर्फ. गलत जानकारी और फेक न्यूज फैलने की आशंका बढ़ती है.

पाकिस्तान सरकार ने कहा कि रविवार को जारी की गई गाइडलाइंस का मकसद मीडिया पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि मीडिया की पुष्टि करने, काम में आसानी और रिपोर्टिंग की जरूरतों में तालमेल बिठाने के लिए एक प्रशासनिक सिस्टम₹ बनाना है. नए नियमों जिन्हें 'फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइंस, 2026' कहा गया है, में यह नहीं बताया गया है कि इजाजत (जिसे 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफि केट' या एनओसी कहा जाता है) मिलने में कितना समय लग सकता है.विदेशी पत्रकारों को पहले से ही एनओसी की जरूरत होती है और उन्हें इजाजत के लिए महीनों इंतजार करना पड़ सकता है. या कभी कोई जवाब नहीं मिलता , जिससे 24 करोड़ की आबादी वाले देश में ग्राउंड लेवल से ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्टिंग करने की उनकी क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है.इसलिए जानकारी की पुष्टि करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया संस्थान अक्सर पाकिस्तानी नागरिकों पर निर्भर रहते हैं, जो पेशावर या क्वेटा जैसे शहरों में आसानी से जा सकते हैं या वहीं स्थायी रूप से रहते हैं.इन नए नियमों के तहत, उन तीन खास शहरों के बाहर रहने वाले फ्रीलांसर्स को भी किसी स्टोरी को कवर करने के लिए एनओसी लेनी होगी.

'डॉन' अखबार के संपादक जफर अब्बास ने कहा, ₹ये बेतुकी पाबंदियां हैं और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं.मैंने इस देश में 40 से ज्यादा सालों तक पत्रकार के तौर पर काम किया है और दो सैन्य शासकों और कई तानाशाही वाले नागरिक शासनों के दौर में भी रिपोर्टिंग की है, लेकिन ऐसी पाबंदियां कभी नहीं देखीं.पत्रकारों से तीन बड़े शहरों के बाहर यात्रा करने के लिए एनओसी मांगना न केवल कहीं भी आने-जाने की आजादी को कमजोर करता है, बल्कि प्रेस की आजादी को भी प्रभावित करता है.\हालांकि पाकिस्तान सरकार का कहना है कि यह लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह से रोक नहीं है.गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि अगर पत्रकार ₹पाकिस्तान की विचारधारा, संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उनका एक्रेडिटेशन (सरकारी मान्यता) रद्द किया जा सकता है.खोखर इसे अस्पष्ट बताते हैं और सवाल उठाते हैं कि इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है.

लेकिन सरकार का कहना है कि एक्रेडिटेशन के किसी भी सिस्टम में कार्रवाई करने की क्षमता होनी चाहिए, खासकर तब जब ₹एक्रेडिटेशन लिया हुआ व्यक्ति ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था पर असर डालती हों.सुप्रीम कोर्ट के वकील सलाहुद्दीन अहमद के मुताबिक, इन गाइडलाइंस को सहारा देने वाला कोई कानूनी ढांचा नहीं है. अहमद कहते हैं, ₹ये 'गाइडलाइंस' सिर्फ. एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं और इन्हें किसी कानून का वैध समर्थन हासिल नहीं है.इनमें रूल्स ऑफ बिजनेस का ज़िक्र है. वे नियम सिर्फ. सरकार के अंदरूनी कामकाज को रेगुलेट करने के लिए होते हैं, न कि दूसरों पर कानूनी ज़िम्मेदारियां थोपने के लिए.साफ तौर पर ये गाइडलाइंस पाकिस्तान में स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर और रोक लगाने की एक जल्दबाजी में और बिना सोचे-समझे की गई कोशिश हैं.वहीं सरकार के मुताबिक, ये गाइडलाइंस 'रूल्स ऑफ बिजनेस' के तहत इस्तेमाल की जाती हैं. चूंकि सूचना मंत्रालय का 'एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग' विदेशी मीडिया के मामलों को देखता है, इसलिए ये गाइडलाइंस विदेशी मीडिया के साथ मंत्रालय के प्रशासनिक संबंधों को नियंत्रित करती हैं.अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों का एक समूह और पाकिस्तान की 'फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स' के अध्यक्ष, सूचना मंत्री से मिलकर अपनी चिंताएं जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं.अधिकारी कुछ खास जगहों से की जा रही रिपोर्टिंग को लेकर ज्यादा चिंतित नजर आते हैं.सोमवार शाम विदेशी मीडिया संगठनों को 'एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग' से एक व्हाएट्सऐप मैसेज मिला, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुरंत वापस आना होगा और एनओसी के लिए आवेदन करना होगा.इस इलाके में पिछले दो महीनों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं, जिनमें कई लोग मारे गए हैं. यहां स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, जिनका प्रदर्शनकारी बहिष्कार कर रहे हैं. इंटरनेट पर लगी पाबंदियों के कारण जानकारी की पुष्टि करना मुश्किल हो गया है.यह संदेश मंत्रालय की ओर से तब भेजा गया जब बीबीसी समेत कई इंटरनेशनल न्यूज आउटलेट्स ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अंदर से रिपोर्ट प्रकाशित कीं.

इस हफ़्ते की शुरूआत में पाकिस्तान में अल जजीरा की वेबसाइट नहीं खुल रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने क्षेत्रीय राजधानी से उनके संवाददाता की रिपोर्ट को ₹यलो जर्नलिज्म₹ (सनसनीखेज रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द) करार दिया था. इस समाचार साइट पर प्रतिबंध लगाने की कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई है.पाकिस्तान में अनरेस्ट की कवरेज राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला रहा है.

ट्रंप के 'बोर्ड ऑफ पीस' में कौन-कौन शामिल हैं और यह विवादों में क्यों घिरा हुआ है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के साथ एक समझौते में हमास ने ₹पूरी तरह हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है.समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए बोर्ड ने कहा कि एक चरणबद्ध योजना के तहत गजा से इसराइली सेना की पूरी तरह वापसी होगी.गजा के लगभग दो-तिहाई हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले इसराइल ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

'बोर्ड ऑफ पीस' क्या है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 22 जनवरी 2026 को वैश्विक संघर्षों के समाधान के उद्देश्य से ट्रम्प की बोर्ड ऑफ पीस पहल के चार्टर की घोषणा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन, बहरीन के प्रधानमंत्री के दरबार के मंत्री शेख ईसा बिन सलमान बिन हमद अल खलीफा, मोरक्को के विदेश मंत्री नासिर बोरिता, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याजकोव और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के साथ बैठे.इस पहल का प्रस्ताव सबसे पहले सितंबर 2025 के आखिर में रखा गया था, जो इसराइल और हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और गजा के पुनर्निर्माण की देखरेख करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना का हिस्सा था.बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव ने इसका स्वागत और समर्थन किया.

हालांकि, इसके चार्टर में गजा या फलस्तीनी क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, जिससे यह आशंका पैदा हो रही है कि इसका दायरा व्यापक हो सकता है और यह उन कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र करता आया है.

इसे औपचारिक रूप से चार महीने बाद, 22 जनवरी को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान लॉन्च किया गया था.राष्ट्रपति ट्रंप ने दावोस में कहा था, ₹एक बार यह बोर्ड पूरी तरह से गठित हो जाए, तो हम लगभग वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं. और हम इसे संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से करेंगे. हालांकि आलोचकों का कहना है कि ऐसा लगता है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के कुछ कार्यों को बदलने के लिए बनाया गया है.मौजूदा स्ट्रक्चर के मुताबिक, ट्रंप आजीवन बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे, जिससे उन्हें व्यापक निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त होगा.अमेरिकी राष्ट्रपति ने लगातार इस बोर्ड को संघर्ष समाधान पर केंद्रित एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में प्रस्तुत किया है.

इसकी स्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर का शुल्क लगता है.

कौन-कौन शामिल होने के लिए सहमत हुआ है?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 22 जनवरी 2026 को दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के दौरान नीचे अपने हस्ताक्षर वाला एक बड़ा मुद्रित बयान पकड़े हुए हैं. वह मुस्कुरा रहे हैं और दो पृष्ठों के इस बयान को, जो एक प्रदर्शनी पुस्तिका में बंधा हुआ है, दोनों हाथों से पकड़े हुए हैं. व्हाइट हाउस ने 60 देशों को आमंत्रित किया था. इनमें से 20 से अधिक देश इसमें शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं, जिनमें इसराइल, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्त्र शामिल हैं.ब्रिटेन और फ्रांस समेत अमेरिका के किसी भी प्रमुख यूरोपीय सहयोगी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया है, और कई देशों ने चिंता जताई है कि यह पहल संयुक्त राष्ट्र को हाशिए पर धकेल सकती है. अन्य देशों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.इस साल की शुरूआत में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना कोई स्पष्टीकरण दिए कनाडा को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया. कनाडा ने सदस्यता लेने में रुचि दिखाई थी, लेकिन उसने 1 अरब डॉलर की सदस्यता फीस का भुगतान करने से मना किया था.ट्रंप ने पुतिन को भी निमंत्रण दिया था, लेकिन इसके बावजूद चीन और रूस दोनों ही इस संस्था में शामिल नहीं हुए.ट्रंप ने कहा है कि स्थायी सदस्यता शुल्क गजा के पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित किया जाएगा.फरवरी में बोर्ड की उद्घाटन बैठक में, ट्रंप ने कहा कि सदस्य देशों ने हमास के हथियार छोड़ने के बाद गजा के पुनर्निर्माण के लिए 7 अरब डॉलर का योगदान दिया था.अप्रैल में, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह गजा पर बोर्ड के साथ सहयोग कर रहे हैं.इस महीने की शुरूआत में, बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा था कि गजा में फलस्तीनियों के लिए एक पायलट ह्यूमेनिटेरियन जोन बनाया जाएगा.

3 अप्रैल 2025 को स्पेन के ग्रेनाडा में आयोजित भूमध्यसागरीय क्षेत्र के भविष्य पर एक मंच पर खड़ी सुइका भाषण दे रही हैं. उन्होंने गहरे रंग का टॉप पहना है और भूरे रंग के चश्मे और भूरे बाल हैं. वह कई झंडों के सामने खड़ी हैं.इस पूरी व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, जिसके पास कूटनीति और निवेश से जुड़े फैसलों की मुख्य ज़िम्मेदारी होगी.

वहीं, गजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड, नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा पर निगरानी रखेगी. यह फलस्तीनी विशेषज्ञों (टेक्नोक्रेट्स) का एक निकाय है, जो गजा में अस्थायी प्रशासन संभालेगा और पुनर्निर्माण के काम का समन्वय करेगा.

पुरानी रंजिश ने लिया हिंसक रूप, युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लाठियां भी बरामद कर ली हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता के साथ की गई और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 13 जुलाई 2026 की रात करीब 10 बजे की है। ग्राम गौरीपुर निवासी मटुकधारी यादव ने प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि ग्राम कंचनपुर निवासी रविन्द्र रजक उनकी दुकान पर पेट्रोल के उधार पैसे लेने आया था। इसी दौरान वहां पहले से पुरानी रंजिश रखने वाले कुछ लोग भी पहुंच गए और देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शिकायत के मुताबिक, लक्ष्मण यादव, संदीप यादव, जमुना प्रसाद यादव और कमलेश यादव लाठी-डंडों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। आरोप है कि चारों ने पुरानी दुश्मनी के चलते रविन्द्र रजक को घेर लिया और जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने लाठियों से लगातार वार किए, जिससे रविन्द्र रजक गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े।

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। रविन्द्र रजक को सबसे पहले प्रेमनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी रहा। घटना की सूचना मिलते ही प्रेमनगर थाना पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 87/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला कायम किया और जांच शुरू की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर प्रेमनगर थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। सीधे सरकार तक पहुंचाएं चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई लाठियां भी बरामद कर जब्त कर लीं, जिन्हें मामले के अहम साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी प्रकार की पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद का समाधान कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की है। इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख विजय तथा कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन की भारत प्रमुख स्मिता रांधे से मुलाकात कर बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, कौशल आधारित प्रशिक्षण देने तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। यह पहल बच्चों को केवल संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की दिशा देने का प्रयास है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि ₹अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। हमारा प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाला प्रत्येक बच्चा आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े।₹ अ'२ङ्क फ्राीं - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्रांति से बदल रही प्रदेश की तस्वीर उन्होंने बताया कि लगभग एक वर्ष पूर्व सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों के सामाजिक पुनर्वास के लिए यह पहल प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है। अब इसे विस्तार देते हुए राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा औद्योगिक घरानों के सहयोग से बच्चों के समग्र विकास और प्रभावी पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

नायब तहसीलदार और जनपद सदस्य पर गंभीर आरोप...रकम डकारने के बाद रजिस्ट्री से मुकरे

आरंगः आरंग क्षेत्र के प्रभावशाली जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रायपुर के निवासी ने मांडले बंधुओं पर जमीन सौदे में पूरी रकम लेकर भी रजिस्ट्री नहीं करने और रकम नहीं लौटाए जाने का आरोप लगाया है। राजधानी रायपुर के निवासी कुलदीप पाण्डेय ने आरंग में एक पत्रकार वार्ता लेकर आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में उन्होंने भानसोज (आरंग) स्थित एक भूमि को खरीदने के लिए जमीन मालिकों राज आशीष मांडले (नायब तहसीलदार), अमर आशीष मांडले (जनपद सदस्य, आरंग), त्रिविहार आशीष मांडले और अगरबाई मांडले के साथ विधिवत अनुबंध किया था। इस सौदे के तहत उन्होंने कुल 1.01 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिसमें से 88 लाख रुपये बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से और 13 लाख रुपये नकद दिए गए थे। इस भुगतान का स्पष्ट उल्लेख एग्रीमेंट के दस्तावेजों में भी दर्ज है। इसके अलावा प्रारंभिक एग्रीमेंट में राकेश कुमार बागरेचा और शशांग बागरेचा भी पक्षकार के रूप में शामिल रहे हैं। एग्रीमेंट के कुछ महीनों बाद जनपद सदस्य अमर आशीष मांडले ने खुद पीड़ित के घर आकर सौदा आगे न बढ़ाने की बात कही। जब पीड़ित ने अपनी राशि वापस मांगी, तो भुगतान करने से इनकार कर दिया गया। अ'२ङ्क फ्राीं - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्रांति से बदल रही प्रदेश की तस्वीर इसके बाद पीड़ित ने सभी पक्षों को कानूनी नोटिस भेजा गया। नोटिस के जवाब में विक्रेताओं ने एग्रीमेंट के अनुसार रजिस्ट्री कराने की सहमति दी, लेकिन साथ में एक शर्त भी जोड़ दी कि सीमांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक साथ रजिस्ट्री कराई जाएगी। फसल और सीमांकन का बहाना बनाकर लगभग एक वर्ष तक मामला टाला जाता रहा। पीड़ित का आरोप है कि सीमांकन और तय समय सीमा बीत जाने के बाद भी जब रजिस्ट्री नहीं हुई, तो अब आरोपी उनसे 30 से 40 लाख रुपये अतिरिक्त देने की नाजायज मांग कर रहे हैं। विरोध करने पर जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचकर पैसे लौटाने की बात कही जा रही है। पीड़ित कुलदीप पाण्डेय ने बताया कि इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक (ढ) कार्यालय, रायपुर तथा आरंग थाना में लगभग 2 महीने पहले दी जा चुकी है। इसके बावजूद आज तक पुलिस ने उनके खिलाफ प्राथमिक दर्ज (त्रक्षक्र) नहीं की है।

नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली आजीवन कारावास

धमतरीः पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में महिला एवं बाल अपराधों के प्रकरणों में त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर आरोपियों को कठोर सजा दिलाने हेतु धमतरी पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना केरेगांव के अपराध क्रमांक 20/2025, विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 54/2025 में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी/), धमतरी द्वारा आरोपी राकेश मंडावी, पिता स्व. आत्माराम मंडावी, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम सियादेही, थाना केरेगांव, जिला धमतरी को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर सजा से दंडित किया गया है। मान.न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 87 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास,अर्थात शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक कारावास की सजा एवं कुल 5,000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी।

एकलव्य स्कूल हॉस्टल में 9वीं के छात्र ने लगाई फांसी, फैली सनसनी

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित पलाड़ी कला के एकलव्य आवासीय विद्यालय से गुरुवार को एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 15 वर्षीय छात्र ने हॉस्टल के टॉयलेट में फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंचे और उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार प्रताड़ना और डांट-फटकार के कारण उनका बेटा मानसिक तनाव में था। परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, निलंबन और आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का हर पहलू से पता लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृत छात्र की पहचान ग्राम बासीन निवासी ओमेश कुमार कंवर (15) के रूप में हुई है। वह पलाड़ी कला स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र था और विद्यालय के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता किसान हैं और बेटे की बेहतर शिक्षा के लिए उसे आवासीय विद्यालय में दाखिला दिलाया था। गुरुवार सुबह हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों ने टॉयलेट के अंदर ओमेश को फंदे पर लटका देखा। यह दृश्य देखकर छात्रों में अफरा-तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना विद्यालय के प्राचार्य मनोज गुप्ता और अन्य कर्मचारियों को दी गई। सूचना मिलते ही स्कूल प्रबंधन मौके पर पहुंचा और छात्र को फंदे से नीचे उतारकर तत्काल जिला अस्पताल सक्ती ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बाराद्वार थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा घटनास्थल से मिले साक्ष्यों की जांच की जा रही है। साथ ही छात्र के साथ पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और हॉस्टल कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। छात्र की मौत के बाद परिजनों ने विद्यालय के प्राचार्य मनोज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्राचार्य छोटी-छोटी बातों पर छात्रों को डांटते थे और ओमेश को भी लगातार प्रताड़ित किया जाता था। परिजनों का आरोप है कि इसी मानसिक दबाव और प्रताड़ना के कारण छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि प्राचार्य को तत्काल निलंबित किया जाए,

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सौर ऊर्जा क्रांति से बदल रही प्रदेश की तस्वीर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण का नया अध्याय लिख रही है। यह योजना केवल बिजली बिल में राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा को जन-जन तक पहुंचाकर हरित भविष्य के निर्माण की मजबूत आधारशिला भी बन रही है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा निवासी लखन लाल कश्यप इस परिवर्तन की सशक्त मिसाल बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेकर उन्होंने अपने घर की छत पर 5 किलोवॉट क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराया है। इस संयंत्र के स्थापित होने के बाद उनका मासिक बिजली बिल पूरी तरह शून्य हो गया है। इससे जहां परिवार की नियमित मासिक बचत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। लखन लाल कश्यप ने बताया कि योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने आवेदन किया। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके घर पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया गया। इस कार्य में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान प्राप्त होने से संयंत्र की स्थापना पर आने वाला आर्थिक व्यय काफी कम हो गया। सरकार की इस सहायता ने सौर ऊर्जा अपनाने का उनका सपना सहज और किफायती बना दिया। उन्होंने बताया कि पहले प्रत्येक माह बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त भार पड़ता था। अब सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है। इससे होने वाली बचत का उपयोग परिवार की अन्य आवश्यकताओं में किया जा रहा है। साथ ही उन्हें यह संतोष भी है कि वे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से प्रदूषण कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं। आपके पास, संदिग्ध मामलों की सूचना सीधे सरकार तक पहुंचाएं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने तथा आम नागरिकों तक स्वच्छ ऊर्जा के लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के अधिकाधिक परिवार सौर ऊर्जा से जुड़ रहे हैं और बिजली पर होने वाले मासिक खर्च में उल्लेखनीय कमी ला रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को भी मजबूती मिल रही है। लखन लाल कश्यप का कहना है कि सौर ऊर्जा भविष्य की सबसे भरोसेमंद, किफायती और पर्यावरण हितैषी ऊर्जा है। इससे न केवल आर्थिक बचत होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित होता है। उन्होंने प्रदेश के सभी पात्र परिवारों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराने की अपील की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जनहितकारी योजना ने सौर ऊर्जा को आम नागरिकों की पहुंच में ला दिया है।

सरकार से प्राप्त अनुदान के कारण आर्थिक बोझ काफी कम हुआ और आज वे बिना बिजली बिल की चिंता के स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। उनके अनुसार यह योजना आर्थिक बचत, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण तीनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा करने वाली दूरदर्शी पहल है।

टीबी के खिलाफ लड़ाई में आगे आएं, बनें किसी मरीज की उम्मीद

रायपुरः टीबी केवल एक बीमारी नहीं है। यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक उपेक्षा से जुड़ी ऐसी चुनौती है, जो हर साल हजारों परिवारों को आर्थिक और मानसिक संकट में धकेल देती है। जब कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित होता है, तब उसके सामने केवल दवा लेने की चुनौती नहीं होती, बल्कि पौष्टिक भोजन जुटाने, नियमित उपचार जारी रखने और सामाजिक भेदभाव से लड़ने जैसी अनेक कठिनाइयाँ भी खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि देशव्यापी प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में ₹निक्षय मित्र₹ की अवधारणा को विशेष महत्व दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के उपचार में दवा जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है पर्याप्त पोषण। लेकिन दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। कई मरीज केवल इसलिए उपचार बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास पोषणयुक्त भोजन की व्यवस्था नहीं होती। ऐसे समय में निक्षय मित्र न केवल पोषण सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि मरीजों के मनोबल को भी मजबूत बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सामने आई है। जिले के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजातियों (ढश्ळत्र्ह्व) के बीच स्वास्थ्य एवं सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यरत जिला डाटा प्रबंधक निरंजन प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2024 से निक्षय मित्र के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने न केवल पीवीटीजी समुदाय के 19 टीबी मरीजों को गोद लिया, बल्कि जिले के कुल 60 टीबी मरीजों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं आवश्यक सहयोग प्रदान कर उपचार की राह में उनका साथ निभाया। जशपुर के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में टीबी की रोकथाम, समय पर पहचान और उपचार सुनिश्चित करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण मरीज अक्सर उपचार में देरी कर देते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मरीजों को पोषण सहायता, स्वास्थ्य परामर्श और निरंतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया,

एक्ट्रेस जिया शंकर ने की बॉयफ्रेंड से सगाई:करण के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की; बोलीं- अचानक मिला मेरा सच्चा प्यार

एक्ट्रेस और 'बिग बॉस डळळ 2' की पूर्व कंटेस्टेंट जिया शंकर ने अपने बॉयफ्रेंड करण के साथ सगाई कर ली है। जिया ने सोशल मीडिया पर सगाई की तस्वीरें शेयर करके अपने रिश्ते का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है।

सनसेट के दौरान आउटडोर लोकेशन पर हुए इस प्रपोजल की झलकियों के साथ जिया ने अपने मंगेतर के लिए एक इमोशनल नोट भी लिखा है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैन्स और दोस्त कपल को बधाइयां दे रहे हैं।

जिया शंकर और उनके बॉयफ्रेंड करण धनक।

सनसेट के बीच मिला सरप्राइज प्रपोजल शेयर की गई तस्वीरों में जिया और करण एक-दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। करण ने जिया को डूबते सूरज की रोशनी में एक आउटडोर लोकेशन पर अंगूठी पहनाकर प्रपोज किया।

एक फोटो में जिया सरप्राइज होकर अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग दिखाती नजर आ रही हैं। इस खास मौके पर जिया ने पेस्टल येलो कलर का सैटिन गाउन पहना था, जबकि करण बेज शर्ट और व्हाइट ट्राउजर में नजर आए।

बोलीं- हजारों मील दूर रहकर भी घर जैसा अहसास हुआ जिया ने सोशल मीडिया पर करण के नाम एक भावुक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, ₹हो सकता है कि यह सच हो, आपको प्यार तब मिलता है जब आप इसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। भले ही तुम मुझसे हजारों मील दूर थे, लेकिन तुमसे हुई हर बातचीत ने घर जैसा अहसास कराया।₹ जिया ने आगे लिखा कि यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हर दिन एक-दूसरे को चुना। उन्होंने करण को अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हुए उनके साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने की बात कही।बिजनेसमैन हैं करण धनक जिया शंकर एक जानी-मानी भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरूआत साल 2013 में रीजनल फिल्मों से की थी और बाद में 'मेरी हानिकारक बीवी', 'काटेलाल एंड संस' और 'पिशाचिनी' जैसे लोकप्रिय टीवी सीरियल्स से घर-घर में अपनी पहचान बनाई। इसके अलावा उन्होंने सुपरहिट मराठी फिल्म 'वेड' और रियलिटी शो 'बिग बॉस डळळ 2' के जरिए काफी लोकप्रियता हासिल की। वहीं उनके मंगेतर करण धनक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अमेरिका (वर) में स्थित एक बिजनेसमैन (एंट्रेप्रेन्योर) और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं।

शोएब से शादी के लिए दीपिका कक्कड़ ने नहीं अपनाया था इस्लाम

दीपिका कक्कड़ की को-स्टार जयति भाटिया ने खुलासा किया कि दीपिका ने शादी के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए इस्लाम कबूल किया था. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि आखिर कब दीपिका ने ये तय कर लिया था कि उन्हें धर्म बदलना है. दीपिका कक्कड़. छोटे पर्दे का वो नाम जिन्हें ससुराल सिमर का से फेम मिला. मगर पिछले कुछ सालों से वह टीवी से दूर हैं. मगर यूट्यूबर के तौर पर आज भी हैडलाइंस में छाई रहती हैं. अपने कामकाज के साथ साथ दीपिका कक्कड़ अपनी मैरिज लाइफ की वजह से भी काफी सुर्खियों में रही हैं.

दरअसल दीपिका कक्कड़ ने दूसरी शादी अपने को-एक्टर शोएब इब्राहिम से की. इसके बाद उन्होंने इस्लाम कुबूल किया और दीपिका से फैजा इब्राहिम हो गईं. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि दीपिका ने ये कदम शोएब से शादी के लिए उठाया. मगर अब इस बारे में उनकी एक कोस्टार ने नया खुलासा किया है.दीपिका कक्कड़ के इस्लाम कुबूल करने पर जयति भाटिया

रवि किशन के मीम ट्रेंड में यूरोपीय फुटबॉल क्लब ने मारी बाजी, इतना पसंद आया कंटेंट की सांसद ने खुद बरसाया प्यार

गोरखपुर से सांसद और फेमस सेलिब्रिटी रवि किशन की हनक अब भारत पार करके यूरोप पहुंच चुकी है। यूरोपीय फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रवि किशन के वायरल मीम ट्रेंड पर जो खेला है, वह देखकर रवि किशन भी खुद को रोक नहीं पा रहे और कमेंट सेक्शन में उन्होंने खुद रिएक्ट किया है। भारत की संसद में वैसे तो 543 सांसद है, लेकिन हाल के समय में सेलिब्रिटी रवि किशन की पॉपुलैरिटी भारत के बाहर तक पहुंच गई है। यूरोप के एक फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने अपने खिलाड़ियों के साथ रवि किशन की एक ऐस रील शेयर कर दी है। जिसे देखने के बाद रवि किशन भी खुद को उसपर रिएक्ट करने से नहीं रोक पाए। यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है।

अच्छा, वीडियो में है क्या?

देखिए, बीते कुछ दिनों से रवि किशन और उनके पोडकास्ट, इंटरव्यूज आदि के कुछ हिस्सों को काटकर इंटरनेट पर एक मीम ट्रेंड सेट हो चुका है। जहां कुछ लोग उनके मीम्स को देखकर हंसते हैं, तो कुछ लोग उसे किसी संदर्भ से रिलेट करके खुद को कूल समझते हैं। रवि किशन ने भी इंटरनेट की जनता को इनफ (ढेर सारा) कंटेंट दे रखा है। जिसके चलते मीमर्स की लॉफ्टर वाली दुकान भी चल पड़ी है। ऐसे में अब इस यूरोपीय फुटबॉल क्लब ने भी मौका देखते हुए चौंका मार दिया है।

यूरोपीय फुटबॉल क्लब जुवेंटिस ने रवि किशन से प्रेरित जो कंटेंट शेयर किया है उसमें जुवेंटस ने किशन के सबसे लोकप्रिय मीम मोमेंट्स का एक कलेक्शन बनाया है। जैसे कि उनके खूब शेयर किए गए ह्यहेडक्वार्टर्स, लो एंगल और होम फ्रॉम वर्कह्न क्लिप्स शामिल है। बोरुसिया डॉर्टमुंड ने फ्रेंडशिप डे के मौके पर बनाई गई एक अलग रील में उनके मशहूर एक्सप्रेशन में से एक का इस्तेमाल भी किया है। आपको बताते चलें कि इंस्टाग्राम पर जुवेंटस फुटबॉल क्लब के 59 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ फॉलोअर्स है। ऐसे में रवि किशन की ये रील भी जनता को खूब पसंद आ रही है। बात करें रवि किशन की तो उन्होंने भी इस वायरल फ्री' पर दिल वाले इमोजी बनाकर इसपर प्यार बरसाया है।

शाहरुख खान बने देश के सबसे महंगे स्टार, 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह से लेकर अमिताभ और अक्षय भी टॉप 10 में

शाहरुख खान ऐसे भारतीय स्टार बन चुके हैं जिनकी ब्रैंड वैल्यू सबसे अधिक है। वहीं विराट कोहली को पीछे छोड़कर 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस टॉप 10 लिस्ट में आलिया भट्ट हैं लेकिन रणबीर कपूर का नाम नहीं है। जानें अमिताभ और अक्षय कुमार का पोजिशन क्या है।

शाहरुख खान वैल्यूएबल सिलेब्रिटीज

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान एक बार फिर से ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी ब्रैंड वैल्यू सबसे अधिक है। भारत के सबसे महंगे सेलेब्रिटी बन चुके शाहरुख दो ब्लॉकबस्टर फिल्में, एंडोर्समेंट का बढ़ता पोर्टफोलियो उन्हें टॉप पोजिशन पर ले आया है। वहीं 'धुरंधर' स्टार रणवीर सिंह दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है।

पिछले साल के मुकाबले इस साल की रिपोर्ट में बड़े चेंजेज हुए हैं, खासकर टॉप 3 के पोजिशन में। शाहरुख जहां पहले नंबर पर हैं, वहीं रणवीर सिंह 162.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ विराट कोहली को पीछे पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गए हैं। वहीं पिछले साल के पोजिशन की बात करें तो शाहरुख खान तीसरे नंबर पर थे।

विराट कोहली को पछाड़कर रणवीर सिंह दूसरे नंबर पर

बता दें कि एक ही साल में दो बड़ी हिट फिल्में 'जवान', 'पठान' जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद ऐड की दुनिया में उनकी डिमांड काफी बढ़ गई है। उनके ब्रैंड एंडोर्समेंट्स की संख्या पिछली बार के मुकाबले 28 से बढ़कर 36 हो गई है। दूसरे नंबर की बात करें तो 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी के ब्लॉकबस्टर होने के बाद रणवीर सिंह की ब्रैंड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया है। वहीं, पिछले साल नंबर वन पर रह चुके विराट कोहली 158.4 मिलियन डॉलर की वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

छठे पोजिशन पर आलिया भट्ट हैं और सातवें पर दीपिका

इसके बाद कुछ क्रिकेटर्स और फिर छठे पोजिशन पर आलिया भट्टहैं। उनकी ब्रैंड वैल्यू 93.9 मिलियन डॉलर है। वहीं दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में हैं और 89.2 मिलियन डॉलर के साथ वो सातवें और 99.9 मिलियन डॉलर के साथ ऋतिक रोशन आठवें पोजिशन पर हैं।

चाहती हूं मैं भी मां बनूं:पवन सिंह से तलाक केस विवाद के बीच पत्नी IVF सेंटर पहुंचीं, भोजपुरी स्टार चाहते हैं तलाक

भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता इन दिनों चर्चा में है। दोनों का तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। ज्योति अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती हैं, लेकिन पवन सिंह उनसे अलग होना चाहते हैं। इस बीच ज्योति सिंह ने मां बनने की इच्छा जाहिर की है।

हाल ही में ज्योति सिंह एक क्श्त्र्ह सेंटर पहुंचीं। वहां उन्होंने कहा कि मैं भी एक महिला हूं और मेरा भी मन होता है कि मेरा एक बच्चा हो। मैं भी मां बनूं। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है, तो वह इसी सेंटर में आएंगी। यह कहते हुए ज्योति सिंह हंसने लगीं।

क्श्त्र्हसे मां बनने पर क्या बोलीं ज्योति?

जब ज्योति से पूछा गया कि क्या वह भी क्श्त्र्ह के जरिए बच्चा करेंगी, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल, क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं लोगों को जागरूक कर रही हूं, तो भविष्य में मुझे ऐसा लगा तो मैं जरूर क्श्त्र्ह से मां बनूंगी। ज्योति की बातों से साफ है कि वह मां बनना चाहती हैं, लेकिन मौजूदा हालातों के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही हैं।

घरेलू हिंसा का लगा चुकी हैं आरोप

पवन सिंह ने पहली पत्नी के निधन के बाद 2018 में ज्योति सिंह से शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया था कि पवन सिंह ने जबरदस्ती उनका अबॉर्शन कराया था। हालांकि, पवन सिंह इन सभी आरोपों को हमेशा से नकारते आए हैं।

ज्योति, पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं। अप्रैल 2022 में ज्योति सिंह ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। पवन सिंह ने भी आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई।

25 मार्च को सुलह की कोशिश के लिए कोर्ट में दोनों को हाजिर होना था। पवन सिंह आए लेकिन ज्योति नहीं आई।पवन सिंह आरा फैमिली कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कोर्ट में जज से कहा, ह्न्यायालय जो भी फैसला देगा, मुझे मंजूर होगा।ह्व उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे वन-टाइम सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, ताकि यह मामला जल्द से जल्द समाप्त हो सके।उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह की वजह से मेरा करियर भी प्रभावित हो रहा है, मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूं। इसी वजह से मैं अब इस रिश्ते से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। मैं ज्योति सिंह से तलाक चाहता हूं। आगे उन्होंने कहा, ह्नशादी के बाद से ही मुझे लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ज्योति ने न सिर्फ मुझे परेशान किया, बल्कि मेरे परिवार को भी क्रूर तरीके से तोड़ने की कोशिश की है। इस रिश्ते का असर मेरे करियर पर भी पड़ रहा है। मैं ठीक से अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूं। अब साथ रहने का कोई चांस नहीं है।

पहली पत्नी ने 2015 में किया था सुसाइड

बता दें कि पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम सिंह ने साल 2015 में आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद भोजपुरी सुपर स्टार पवन सिंह के अफेयर की चर्चा जाने-माने भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के साथ होने लगी।

रणबीर कपूर माफी मांगे', निकिता रावल ने जमकर कोसा-बीफ खाने वाला घटिया इंसान भगवान राम कैसे बन सकता है?

एक्ट्रेस निकिता रावल ने 'रामायणम्' में राम के किरदार में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं और कहा कि एक्टर जब तक माफी नहीं मांगेंगे, वो उनके खिलाफ बायकॉट ट्रेंड चलाती रहेंगी। एक्ट्रेस निकिता रावल ने रणबीर कपूर पर निशाना साधा है और उनसे लोगों से माफी मांगने के लिए कहा है। मामला नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में रणबीर कपूर की कास्टिंग से जुड़ा है। फिल्म में रणबीर, भगवान श्रीराम के किरदार में हैं और इसी लेकर ट्रेलर रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया दो भागों में बंटा हुआ है। बहुत से लोगों ने रणबीर की राम के किरदार में कास्टिंग पर सवाल उठाए हैं कहना है कि वह इस किरदार के लिए फिट नहीं। इस बीच निकिता रावल ने भी रिएक्ट किया है और रणबीर से उनके एक पुराने बयान को लेकर माफी मांगने को कहा है। साथ ही कहा कि अगर रणबीर ने माफी नहीं मांगी, तो वह उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाती रहेंगी।निकिता रावल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि भगवान राम का किरदार निभाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जो एक्टिंग से कहीं ज्यादा बढ़कर है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों लोगों की भावना है, जिसे लोग पवित्र आत्मा के साथ देखते हैं। भगवान राम सिर्फ पौराणिक कथाओं के किरदार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आस्था और मूल्यों के प्रतीक हैं। उनका मानना है कि ऐसे प्रभु का किरदार निभाने के लिए चुने गए कलाकारों को उस भूमिका से जुड़ी भावनाओं और दर्शकों की उम्मीदों का पता होना चाहिए।

'जब तक माफी नहीं मांगेगा बायकॉट ट्रेंड चलाती रहूंगी'

निकिता रावल ने 'बॉलीवुड मासकट' को दिए इंटरव्यू में रणबीर की राम के किरदार में कास्टिंग पर बात करते हुए उनके बीफ खाने वाले पुराने बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक्टर को माफी मांगनी चाहिए। निकिता रावल से रणबीर के बीफ वाले बयान पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में वह बोलीं, 'जिसने लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। सीधा बोल रहा है कि भई में बीफ खाता हूं...और फिर वही वही श्रीराम का किरदार निभा रहा है। इसको क्या मैसेज देंगे? मुझे लगता है कि यार इसको बायकॉट कर दो। मैं चलाती रहूंगी। और अगर उसको जरा सा भी लगता है कि उससे गलती हुई है, या इस कैरेक्टर के पहले या बाद में, जो भी उसको समझ आता है, वो आकर उन लाखों लोगों से माफी मांगे, जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है,

59 साल पहले बना सावन का गाना, सुनील दत्त-नूतन की केमिस्ट्री, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज का जादू

दिल्लीः

बॉलीवुड में आपको हर मौसम, हर मिजाज और हर इमोशन से जुड़े गीत मिल जाएंगे. वहीं अब जब सावन का महीना है तो इसके आते ही बॉलीवुड के कई गाने प्लेलिस्ट में वापस से लौट आते हैं. इन्हीं में से एक गाना है जो 59 साल बाद भी उतना ही पसंद किया जाता है. साल 1967 में आई फिल्म 'मिलन' का फेमस गाना 'सावन का महीना पवन करे शोर' गाना आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है. इस गाने में सुनील दत्त और नूतन की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है.आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का संगीत

साल 1967 में आई फिल्म 'मिलन' के गाने 'सावन का महीना पवन करे शोर' गाने के बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे. गाने के आसान और दिल को छू लेने बोल ने इसको खास बना दिया था. वहीं गाने का संगीत मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने तैयार किया. लता मंगेशकर और मुकेश की दिल को छू लेने वाली आवाज ने इस गाने को ऐसा बना दिया कि ये हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा बारिश के गानों में गिना जाने लगा.

लता-मुकेश की आवाज ने गाने को बनाया कल्ट

गाने के बोल और दमदार संगीत के साथ लता और मुकेश की आवाज ने इस गाने को सदाबहार बना दिया. दोनों ने अपनी आवाज का जादू ऐसा चलाया कि ये रोमांटिक गाना हर पीढ़ी की पसंद बन गया. आज भी जब पुराने सदाबहार गीतों की बात आती है तो ये गाना लिस्ट में जरूर शामिल होता है. साइकिल पर शूट हुआ ये 54 साल पुराना गाना, मनोज कुमार ने ली सरकार से टक्कर, आज भी दिल चीर देती है मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज 40 साल से अकेली रह रही सुशांत सिंह राजपूत की ऑनस्क्रीन मां, 80 की उम्र में भी कर रही काम, बोलीं- मर गई तो क्या किसी को पता चलेगा फिल्म 'मिलन' का निर्देशन अदुरथी सुब्बा राव ने किया था. ये उस दौर की हिट फिल्मों में शामिल थी. फिल्म की कहानी के साथ-साथ इसके गानों को भी दर्शकों ने खूब प्यार दिया. फिल्म की रिलीज के बाद इसका गाना 'सावन का महीना पवन करे शोर' लोगों की जुबान पर चढ़ गया था.

RNI Reg. No. CHHHIN/2013/49327
द शूटर
हिन्दी दैनिक

महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, ओड़गी से शुरू होगा जनजागरण अभियान

ओड़गी, 06 अगस्त 2026, द शूटर। बिजली का बिल अब केवल एक मासिक खर्च नहीं, बल्कि आम परिवारों की चिंता का विषय बनता जा रहा है। बढ़ती बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं के बीच बढ़ रही नाराजगी को मुद्दा बनाते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओड़गी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठनात्मक बैठक आयोजित कर चरणबद्ध जन आंदोलन की रणनीति तय की।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि लगातार बढ़ रही बिजली दरों ने किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया है। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर प्रदेशभर से उपभोक्ताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल है। उनका कहना था कि जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस गांव-गांव तक लोगों के बीच पहुंचेगी और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाएगी।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओड़गी द्वारा व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड-वार्ड पहुंचकर लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे तथा चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से जनभावनाओं को शासन तक पहुंचाया जाएगा।

बैठक में प्रमुख मांगों में बढ़ी हुई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं वहां पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग प्रमुख रही। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना को पुनः शुरू करने और बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। संगठनात्मक मजबूती पर भी विशेष जोर देते हुए बूथ स्तर तक कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया। विभिन्न मंडलों और प्रकोष्ठों में आवश्यक नियुक्तियों एवं जिम्मेदारियों से जुड़े प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किए गए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लवकेश गुर्जर ने पदाधिकारियों और कार्यकताओं का आह्वान करते हुए कहा कि संगठन की ताकत तभी सार्थक होगी जब वह जनता के बीच रहकर उनके अधिकारों और जनहित के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाए। बैठक में प्रमुख रूप से रामकुमार बंछोर, राजेंद्र यादव, धर्मप्रसाद राजवाड़े, चंद्रभान राजवाड़े, धर्मेंद्र यादव, राजाराम यादव, देवनायण चेरवा, हेमेंद्र गुर्जर, कृष्णा गुर्जर, प्रवीण सिंह, खुशीराम पाण्डेय, प्रीति जायसवाल, जगदीश रक्सेल, लालू जायसवाल, रविशंकर गुर्जर, संजय कुमार जैन, ताराचंद गुर्जर, अरुण राजवाड़े, प्रताप सिंह, धर्मजीत सिंह, संतोष राजवाड़े, विजय रक्सेल, रामकुमार राजवाड़े, विभव गुर्जर, हरकेश राजवाड़े, औवलेंद्र गुर्जर, दीपक गुप्ता, सुदामा यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

गांवों की डिजिटल चौपाल से राज्य स्तर तक पहुंची पहचान: सूरजपुर के दो वीएलई बने टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई, राज्य स्तरीय सम्मान से बढ़ाया जिले का मान

सूरजपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। ग्रामीण अंचलों में जहां कभी छोटी-छोटी शासकीय सेवाओं के लिए लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, वहीं आज कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) गांवों में ही शासन और नागरिकों के बीच मजबूत डिजिटल सेतु बन चुके हैं। इन्हीं सेवाओं को समर्पित भाव से लोगों तक पहुंचाने वाले सूरजपुर जिले के दो ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) ने अपनी मेहनत और उत्कृष्ट कार्यशैली के दम पर राज्य स्तर पर जिले का गौरव बढ़ाया है।राजधानी रायपुर में 17वें सीएससी दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में शैलेन्द्र कुमार कुशवाहा एवं प्रशांत कुमार सरकार को टॉप ट्रांजैक्टिंग वीएलई (मल्टी सर्विस ग्रेड) श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय, डिजिटल, बैंकिंग एवं जनसेवा संबंधी सुविधाएं प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।दोनों वीएलई ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सहज और सुलभ बनाते हुए हजारों लोगों तक शासन की योजनाओं और ऑनलाइन सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। उनके कार्यों ने न केवल आम नागरिकों का समय और धन बचाया, बल्कि डिजिटल इंडिया की अवधारणा को गांव-गांव तक साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उल्लेखनीय है कि कॉमन सर्विस सेंटर आज ग्रामीण भारत में शासन और जनता के बीच विश्वास का मजबूत माध्यम बन चुके हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, बैंकिंग सेवाएं, पेंशन, बीमा तथा अन्य अनेक ऑनलाइन सुविधाएं अब ग्रामीणों को उनके अपने गांव में ही उपलब्ध हो रही हैं। कु लमिलाकर सूरजपुर जिले के इन दोनों वीएलई को मिला राज्य स्तरीय सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे जिले और सीएससी परिवार के लिए गर्व का विषय भी है। उनकी इस सफलता से अन्य ग्राम स्तरीय उद्यमियों को भी बेहतर सेवाएं देने की प्रेरणा मिलेगी। समारोह में दोनों सम्मानित उद्यमियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

किराये के कमरों से अपने भवन तक पहुंची आंगनबाड़ी, गुरु घासीदास वार्ड में पहली बार बनेगा स्थायी केंद्र

अम्बिकापुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। किसी भी समाज का भविष्य उसके बच्चों से तय होता है और जब उन बच्चों को बेहतर माहौल मिले तो विकास की नींव और मजबूत होती है। वर्षों से किराये के भवनों में संचालित हो रही आंगनबाड़ियों के बीच आखिरकार गुरु घासीदास वार्ड के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वार्ड को अपना पहला स्थायी आंगनबाड़ी भवन मिलने जा रहा है, जिससे छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। गुरु घासीदास वार्ड के पार्षद शुभम जायसवाल के प्रयासों से 12 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पहले आंगनबाड़ी भवन का गुरुवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव, महापौर श्रीमती मंजूषा भगत, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद, सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी तथा एमआईसी सदस्य मनीष सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार गुरु घासीदास वार्ड में कुल तीन आंगनबाड़ियां संचालित हैं और अब तक तीनों किराये के भवनों में चल रही थीं। ऐसे में पहले स्थायी भवन का निर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है।इसी अवसर पर वार्ड की जर्जर नालियों के मरम्मत कार्य का भी शिलान्यास किया गया। लगभग 3 लाख 20 हजार रुपये की लागत से होने वाले इस कार्य के पूरा होने के बाद जलभराव और गंदगी जैसी समस्याओं से भी वार्डवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा, पूर्व पार्षद शेखर झरिया, उमा देवी राजवाड़े, श्रीकांत सिन्हा, मिथुन सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, सूरज तिवारी, मुकेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, कबीर गोस्वामी, आशुतोष मिश्रा, सुरेश सोनी, सुरेंद्र सोनी, लाल विजय, समीर सक्षम, साहिल, महेंद्र सूर्यवंशी, वनस झा, आर्यन सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। वार्डवासियों ने उम्मीद जताई कि आंगनबाड़ी भवन बनने के बाद बच्चों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिलेगा, वहीं नाली मरम्मत कार्य से वार्ड की मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार आएगा। विकास के इन दोनों कार्यों से गुरु घासीदास वार्ड में नई शुरूआत की उम्मीद दिखाई देने लगी है।

मृतक की पहचान पर रची गई जमीन हड़पने की साजिश, फर्जी आधार कार्ड बनाकर 30 लाख की भूमि बेचने का आरोप, तीन गिरफ्तार

अम्बिकापुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। जमीन से जुड़े विवाद और फर्जीवाड़े के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बीच सरगुजा पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का पदार्फाश किया है, जिसने वर्षों पहले मृत हो चुके व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल कर उसकी जमीन का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सौदा कर लाखों रुपये का आर्थिक लाभ अर्जित कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के तहत अंजाम दी गई, जिसमें मृतक के नाम पर फर्जी पहचान तैयार कर रजिस्ट्री कराई गई और बाद में उसी जमीन को दोबारा बेच दिया गया।कोतवाली पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता आलोक दुबे की लिखित शिकायत पर जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि

घुटरापारा (मायापुर) स्थित खसरा क्रमांक 356/2 की 0.065 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में मोहरसाय राजवाड़े के नाम दर्ज थी, जिनका निधन वर्ष 1962 में हो चुका था। इसके बावजूद आरोपियों ने एक अन्य व्यक्ति को मोहरसाय बताकर उसकी झूठी पहचान स्थापित की, फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और उसी के आधार पर 25 सितंबर 2025 को जमीन की रजिस्ट्री करा दी।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस सौदे में शामिल लोगों ने रजिस्ट्री के दौरान चेक नंबर केवल औपचारिकता के लिए दर्ज कराए थे। बाद में इसी जमीन को करीब 30 लाख रुपये में अन्य लोगों के नाम बेच दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि सौदे से मिली राशि का कुछ हिस्सा सह-आरोपियों को दिया गया, जबकि शेष रकम मुख्य आरोपी बंटी पटेल उर्फ वर्षित पटेल द्वारा प्राप्त किए जाने के संकेत मिले हैं। विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी अमर सिंह के वास्तविक आधार कार्ड में कूटरचना कर उसका नाम बदलकर मोहरसाय राजवाड़े दशार्या गया। इसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर पंजीयन कार्यालय में पहचान प्रस्तुत कर विक्रय विलेख का निष्पादन कराया गया। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध दस्तावेजों, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हुआ कि आरोपियों ने आपस में मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धोखाधड़ीपूर्वक भूमि का विक्रय कर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया। मामले में थाना कोतवाली में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी राम निवास गुप्ता उर्फ बोखा तथा दो महिला आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों के कथनों के आधार पर रजिस्ट्री में प्रयुक्त चेक, चेकबुक और एक रियल कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले के पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, उप निरीक्षक के.के. यादव, प्रधान आरक्षक छात्रपाल सिंह, महिला आरक्षक सरस्वती पांडेय तथा आरक्षक आनंद गुप्ता और लालबाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बिश्रामपुर में उम्मीद की पटरी पर दौड़ेगी लाइफ लाइन एक्सप्रेस, 16 अगस्त से हजारों मरीजों को मिलेगा नि:शुल्क इलाज

*** नेत्र, कान, दंत, प्लास्टिक एवं अस्थि रोगों की जांच और शल्य चिकित्सा होगी मुफ्त, कलेक्टर ने अधिक से अधिक लोगों से लाभ लेने की अपील**

सूरजपुर/विश्रामपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। आर्थिक तंगी और विशेषज्ञ उपचार की कमी के कारण कई परिवार वर्षों तक बीमारी का दर्द सहने को मजबूर रहते हैं। ऐसे जरूरतमंद मरीजों के लिए इस बार राहत की सौगात लेकर आ रही है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो अस्पताल नहीं बल्कि उम्मीदों से भरी एक चलती-फिरती चिकित्सा सेवा है। बिश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-02 पर 16 अगस्त से 5 सितंबर तक लगने वाले इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और जरूरत पड़ने पर निःशुल्क शल्य चिकित्सा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की 256वीं लाइफ लाइन एक्सप्रेस परियोजना के तहत आयोजित इस शिविर में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। जांच के बाद पात्र मरीजों की निशुल्क सर्जरी भी की जाएगी। शिविर के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 से 21 अगस्त तक नेत्र रोगों, विशेषकर मोतियाबिंद एवं दृष्टिदोष की जांच तथा 17 से 22 अगस्त तक शल्य चिकित्सा की जाएगी। 22 से 27 अगस्त तक कान संबंधी रोगों की जांच एवं ऑडियोमेट्री तथा 23 से 28 अगस्त तक मध्य कर्ण की सर्जरी होगी। 28 से 31 अगस्त तक कटे-फटे होंठ एवं जलने से उत्पन्न विकृतियों के लिए प्लास्टिक

सर्जरी की जांच तथा 29 अगस्त से 1 सितंबर तक ऑपरेशन किए जाएंगे। इसी दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अस्थि विकारों की शल्य चिकित्सा भी होगी। 1 से 5 सितंबर तक दंत रोगों की जांच एवं उपचार किया जाएगा, जबकि 16 से 21 अगस्त के बीच महिलाओं के लिए स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच एवं स्क्रीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों को नेत्र, कान, दंत, प्लास्टिक अथवा अस्थि संबंधी समस्याएं हैं, वे निर्धारित तिथियों में शिविर पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच और उपचार अवश्य कराएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकताओं से भी आग्रह किया कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक इस स्वास्थ्य शिविर की जानकारी पहुंचाएं, ताकि कोई भी मरीज केवल जानकारी के अभाव में उपचार से वंचित न रह जाए। कुलमिलाकर शिविर में आने वाले प्रत्येक मरीज को आधार कार्ड अथवा अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। भर्ती मरीज के साथ केवल एक परिजन को रहने की अनुमति रहेगी। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7039673973 पर संपर्क किया जा सकता है।

अक्टूबर से पहले 58 ग्राम पंचायतों में बदलेगी कचरा प्रबंधन की तस्वीर: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू करने जिला स्तर पर मंथन

सूरजपुर, 06 अगस्त 2026, द शूटर। स्वच्छ और स्वस्थ गांव केवल सरकारी योजनाओं से नहीं, बल्कि जनभागीदारी और जिम्मेदार व्यवहार से बनते हैं। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए सूरजपुर जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़ी पहल की गई। कलेक्टर के निदेर्शानुसार जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में विशेष जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें प्रथम चरण के लिए चयनित 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और घर-घर कचरा संग्रहण एवं पृथक्करण का कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों ने भाग लिया।कार्यशाला में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निदेर्शों के पालन में 1 अप्रैल 2026 से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू किया गया है। जिला पंचायत सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिए कि चयनित सभी 58 ग्राम पंचायतों में

अक्टूबर 2026 से पहले नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएं। इसके लिए प्रत्येक पंचायत को पाक्षिक कार्ययोजना बनाकर निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा।प्रशिक्षण के दौरान प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीला, सूखा, सैनिटरी तथा विशेष या जोखिमपूर्ण कचरे का पृथक संग्रहण, स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करण, खुले में कचरा फेंकने पर रोक, बड़े अपशिष्ट उत्पादकों का चिन्हांकन एवं पंजीयन, कचरा जलाने पर प्रतिबंध तथा उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई जैसे प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कार्यशाला में राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि स्वच्छता अभियान तभी सफल होगा जब पंचायतें इसे जनआंदोलन का स्वरूप दें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ व्यवहार परिवर्तन पर विशेष जोर दिया। सामुदायिक जागरूकता के लिए दीवार लेखन, चौपाल, बैठक, रैली तथा अन्य आईईसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कार्ययोजना भी तैयार की गई। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ ने सभी सरपंचों एवं सचिवों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 की प्रति भी उपलब्ध कराई। देवीपुर, कूंदेत, लांजीत और चुनगुड़ी ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने अनुभव साझा करते हुए समय सीमा के भीतर अपने गांवों को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने का संकल्प व्यक्त किया।कार्यशाला में राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा, जिला समन्वयक (एमसीबी) राजेश जैन, जिला सलाहकार संजय सिंह, सभी विकासखंडों के स्वच्छता अधिकारी, 58 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव तथा स्वच्छाग्राहियों की उपस्थिति रही। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनसहभागिता और पंचायतों की सक्रिय भूमिका से ही स्वच्छ, स्वस्थ और कचरा मुक्त गांवों का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सकेगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- रूपेश दुबे द्वारा आर्यन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, पॉवर हाउस रोड नमना कला अम्बिकापुर, सरगुजा, छ0ग0 से मुद्रित एवं मेन रोड प्रतापपुर, खोरमा, जिला- सूरजपुर, छ0ग0 से प्रकाशित। संपादक- प्रवीण दुबे* (* समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। फोन- 07777271215